लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
6
Parliament Library

[खंड VI में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 40 शनिवार, 15 जुलाई, 1967/24 आषाढ, 1889 (शक)

No. 40—Saturday, July 15, 1967/Asadha 24, 1889 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Adjournment Motion and Calling Attention Notice (Query)	5519
अनुदानों की मांगें जारी	Demands for Grants, 1967-68 Contd.. ..	5520
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय जारी	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation Contd. ..	5520
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	5520
श्रीमती निर्लेप कौर	Shrimati Nirlep Kaur ..	5520
श्री बेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	5522
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu ...	5522
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	5523
श्री सत्यनारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh	5524
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri Kashi Nath Pandey	5524
श्री ब्रह्मानन्दजी	Shri Bramhanandji	5524
श्री राम गोपाल शालवाले	Shri Ram Gopal Shalwale ..	5525
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath ...	5526
श्री लताफत अली खां	Shri Latafat Ali Khan	5526
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	5527
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	Ministry of External Affairs	5534
श्री मी. रु. मसानी	Shri M. R. Masani	5534
श्री सन्त बक्स सिंह	Shri Sant Bux Singh	5536

विषय	Subjects			पृष्ठ/Pages
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	..	...	5537
श्री रा. कृ. सिंह	Shri R. K. Sinha	...	...	5541
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	...	...	5549
श्री मानवेन्द्र शाह	Shri Manabendra Shah	...	...	5551
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	...	...	5553
श्री च. का. भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharaya	...	...	5553
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	..	...	5554
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	...	...	5555–5556
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	...	...	5556
नागा विद्रोहियों द्वारा पुलिस कर्मचारियों की हत्या	Killing of Policemen by Naga Hostiles ...			5556

— ——

लोक-सभा

LOK-SABHA

शनिवार, 15 जुलाई, 1967/24 आषाढ़, 1889 (शक)

Friday, 15 *July*, 1967/*Asadha* 24, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE: ADJOURNMENT MOTION AND CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I would like to know about the fate of adjournment motions moved by us. You were pleased to say that you will decide about it after consultation with the Minister.

Shri Sheo Narain : (Basti): We should also be given a chance to speak.

श्री हेम बरुआ : (मंगलदाई) : कल हमने नागा विद्रोहियों द्वारा 23 पुलिस कर्मचारियों की हत्या के समाचार के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव रखा था, क्या स्थगन प्रस्ताव ध्यान दिलाने वाली सूचना के बादलिया जायेगा अथवा स्थगन प्रस्ताव अभी लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव कार्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। ध्यान दिलाने वाली सूचना कार्य सूची में शामिल कर ली गई है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): May name has not been included in the Calling Attention Notice.

अनुदानों की मांगें–जारी

DEMANDS FOR GRANTS–Contd.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय-जारी

Shri Mrityunjay Prasad (Mahrajganj) : We are not paying proper attention to the green manure. While laying emphasis on hybrid seeds we should not ignore the development of seeds for green manure.

We are not paying any attention to a very important source of inorganic fertilizer. There is iron waste in steel factories which is not utilised. That can be utilised for the manufacture of fertilzers.

Emphasis has been laid on the major irrigation projects during the last few years and a lot of amount has been spent thereon. Still we may not be able to derive the benefits which we expected from them. We should now lay more emphasis on minor irrigation schemes. If a major irrigation project fails to bear fruit, we will have to incur heavy losses but the failture of minor schemes will not put us to such a great loss.

The rats and sparrows cause harm to the crops, but we should not follow the example of China and kill the sparrows. They also help us by eating the insects which cause harm to the crops.

Although we have developed better varieties of wheat which have resulted in increase in production. Still there has not been appreciable increase in total production. It is because we have not differentiated between experimental forms and demonstration forms. We may spend as much as we like on experimental forms but the model forms or demonstration forms should be self-supporting. If they are not self-supporting inspite of best land, bullocks, tractors, seeds, manure and irrigation, they cannot make other farmers to follow from them and learn from them.

श्रीमती निर्लेप कौर (सिगरूर) : चुनाव से एक मास पहले मंत्रि–मण्डल ने अपनी खाद्य नीति की घोषणा की थी ओर कहा था कि देश 1970–71 तक खाद्यान्न के मामले में स्वावलम्बी हो जायेगा परन्तु अब यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार की खाद्य नीति बिल्कुल असफल रही है, फिर भी सरकार विरोधी दलों के सुझाव का केवल इस कारण विरोध करती है कि उसे अपनी नीतियों का समर्थन करना पड़ रहा है, चाहे उनमें कितना ही दोष क्यों न हो। उदाहरण के लिये सभी दलों ने यह मान लिया है कि खण्ड विकास कार्यक्रम पूरी तरह असफल सिद्ध हुए हैं और उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिये। फिर भी मंत्री महोदय उनका समर्थन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह रवैया देश के लिये हानिकार है।

भूमि सुधारों के फलस्वरूप अलाभप्रद भूमियों में कृषि होने लगी है। पहले लाभप्रद एककों में यंत्रीकरण किया जा सकता था तथा खाद और सिंचाई आदि के रूप में धन लगाया जा सकता था। परन्तु सरकार ने उन लाभदायक एककों को नष्ट कर दिया है तथा

नये छोटे एकक संतोषजनक तरीके से कार्य नहीं कर सकते । हम देख रहे हैं कि भूमि के अग्रेतर टुकड़े हो रहे हैं । इस प्रकार हम अपनी खाद्य समस्या हल नहीं कर सकेंगे ।

हमें भूमि के अग्रेतर टुकड़े नहीं होने देना चाहिये । यदि किसी व्यक्ति के चार पुत्र हो तो उसकी मृत्यु के पश्चात एक लड़के को अधिकतम स्वीकृत भूमि मिलनी चाहिये तथा अन्य लड़कों को बाजार मूल्य पर उसका हिस्सा दिया जाना चाहिये । जिस भाई को भूमि मिलती है, उसे 10 तथा 15 वर्षों में शेष राशि का भुगतान कर देना चाहिये ।

मेरा एक अन्य सुझाव यह है कि काश्तकार को मिलकियत का अधिकार मिलना चाहिये ताकि ऋणों के लिये उसके पास प्रत्याभूति रह सके । एक अथवा दो एकड़ भूमि वाला कृषक अथवा काश्तकार कहीं से ऋण नहीं प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसे बताया जाता है कि ऋण के लिये वह प्रर्याप्त प्रत्याभूति नहीं है ।

यह नीति गलत है कि केवल भूमिहीन को ही भूमि दी जाये, चाहे उसे कृषि सम्बन्धी कोई जानकारी हो अथवा न हो । ऐसे लोग भूमि नहीं जोतते बल्कि वे इसे आगे बचने के अवसर की ताक में रहते हैं । भूमिहीन लोगों को सुअर पालने, मुर्गी पालने तथा चमड़े के काम जैसे व्यवसायों के लिये, जिनके लिये हमारे देश में काफी गुंजाइश है, सहायता दी जानी चाहिये । इससे भूमि पर दबाव कम हो जायेगा ।

बहुत से लोगों के विचार में भारतीय कृषक बहुत ही पिछड़े हुए हैं और उन्हें कृषि के बारे में शिक्षा देने की बहुत आवश्यकता है, यह बात स्पष्टतया समझ लेनी चाहिये कि खाद्य समस्या का हल अन्ततः कृषक ही करेंगे न कि योजना आयोग तथा अन्य सरकारी कर्मचारी, जिन्हें कृषि का व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है । हमें कृषक के बारे में अपनी विचारधारा पूर्णतया बदल देनी जाहिये तथा उसे उपयुक्त आदर दिया जाना चाहिये । इसकी बजाय कि उसे सलाह मशवरे दिये जायें, उसे अपेक्षित बीज ओर खाद आदि देकर उसकी सहायता करनी चाहिये । कृषक को सरकार से नियंत्रण, खण्ड तथा क्षेत्र मिले हैं, जिनकी उसे आवश्यकता नहीं है । एक राज्य क्षेत्र खंड बनाने से पंजाब के कृषकों को 25 करोड़ रुपये की हानि हुई है ।

स्वतन्त्रता के 20 वर्ष पश्चात केवल 20 प्रतिशत भूमि की सिंचाई हो सकी है । यदि हम इस क्षेत्र से वह क्षेत्र निकाल दें जिसकी सिंचाई स्वतन्त्रता से पूर्व नहरों द्वारा की जाती थी तथा ऐसे क्षेत्र जिसकी सिंचाई कृषक निजी रूप से नलकूपों द्वारा करता था तो सरकार द्वारा सिंचाई के लिये किया गया कार्य नगण्य ही सिद्ध होगा । वास्तविक योजना वह है जो इसराइल द्वारा की गई है अर्थात मरुस्थल के बीच लहलहाते खेत । मैं समझती हूं कि 20 वर्ष की योजनाओं के बाद हमारी अर्थ व्यवस्था पर अधिक अथवा कम वर्षा का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिये । यदि हमारा सारा आयोजन वर्षा पर ही निर्भर करता है तो योजना आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है । जहां तक संकर बीजों का सम्बन्ध हैं, उनके लिये पानी की अधिक बार आवश्यकता होती है । इसलिये यदि हम चाहते हैं कि इन बीजों का प्रयोग किया जाये तो सरकार को बड़ी मात्रा में नलकूप लगाने चाहिये । हमें चार इंच

मोटी धार छोड़ने वाले लगभग 20,000 नलकूपों की आवश्यकता है, जिन पर लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे । इससे अनाज का उत्पादन प्रति एकड़ कम से कम दो टन बढ़ जायेगा । कुल मिला कर इससे 20 लाख टन की वृद्धि होगी ।

हमें उर्वरकों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और कार्बनिक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिये । किसान को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिये और उसे उद्योग की रीड की हड्डी समझा जाना चाहिये । तभी देश में अन्न की कमी दूर हो सकती है ।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : In the year 1965-66, the production of sugar in our country was 35 lakh tons which fell down to 22 lakh tons in 1966-67. The result was that whereas Government used to release $2\frac{1}{2}$ lakh tons of sugar.-per month in the year 1965-66, but in 1966-67 Government released about $1\frac{1}{2}$ lakh tons of sugar per month. When Government used to realse $2\frac{1}{2}$ lakh tons of sugar no doubt some sugar was sold in black market, but the prices in black market did not go beyond, the margin of Re. 1 or Rs. $1\frac{1}{4}$. But by reducting the quantity of sugar relesed by the Government by 1 lakh tons, the prices in black market range between Rs. 4 & Rs. 6. Why has this situation been brought about ? The canegrowers went in for Gur and Khandsari instead of selling the sugar cane to the sugar mills. The prices of sugar cane paid by the mills were on the low side and were not remunerative for the cane-growers, whereas by turning the sugar-cane into Gur and Khandsari, they got more returns for their produce. All this has resulted into the non-supply of sugar cane to the sugar mills. As a result of this Government is being deprived of a large reveneue in the shape of excise duty, the mill wovers are not getting aducate returns on their investments and the workers are facing unemployment on account of partial or complete closure of mills because of non-supply of sugar-cane. Consumers cannot meet their requirement of sugar and they have to purchase it in the black market. The distributors and the officers responsible for their appointment have largely profited by the present situation.

The distributors have earned huge profits by selling it in the black market. This situation can only be remedied by lifting control on sugar. The grower, the consumer, the mill owner or the Government-none of them stands to any advantage by this control. If complete decontrol is not possible, at least partial decentrol should be enforced.

The zonal system is also no good and should be abolished.

श्री चेंगल राया नायडू (चित्तूर) : मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम अनाज के मामले में 1971 तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे परन्तु मैं नहीं जानता कि वे इसे पूरा कर सकेंगे या नहीं । वित्त मन्त्रालय के सहयोग तथा योजना की ठीक तरह से कार्यान्विति से ही यह आश्वासन पूरा हो सकता है ।

अमरीका हमें चावल नहीं दे सकता है और चावल के आयात के लिये हमें मूल्यवान विदेश मुद्रा खर्च करनी पड़ती है । आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर तथा महाराष्ट्र का लगभग 6 लाख टन चावल दे रहा है और वह भी आयातित चावल से सस्ती दरों पर और हमें विदेशी मुद्रा भी खर्च नहीं करनी पड़ती । आन्ध्र प्रदेश देश की मांग पूरी करने के लिये अधिक चावल पैदा करने के लिये तैयार है परन्तु केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार की सहायता करने के लिये आगे नहीं आ रही है ताकि वह अपनी परियोजनाओं को पूरी कर सके । आन्ध्र प्रदेश में

नागार्जुन सागर परियोजना का काम काफी आगे बढ़ चुका है । उसे यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिये । उससे आन्ध्र प्रदेश सस्ते दर पर देश के लिये चावल पैदा कर सकेगा । महाराष्ट्र और मैसूर के रवैये के कारण इस परियोजना की कार्यान्विति में गतिरोध उत्पन्न हो गये जिसे दूर किया जाना चाहिये । यदि महाराष्ट्र तथा मैसूर अपने यहां कोई परियोजना आरम्भ करना चाहते हैं तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है । महाराष्ट्र में गोदावरी छोटी धारा में बहती है और आन्ध्र तक पहूँचते पहुंचते अन्य नदियों के मिल जाने से यह काफी बड़ा नदी का रूप धारण कर लेती है । उन्हें पानी के बारे में इस तरह का विवाद खड़ा नहीं करना चाहिये ।

छोटी सिंचाई के लिये बजट में रखी गई धनराशि काफी नहीं है । यदि हम वास्तव में देश को 1971 या 1972 तक आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें छोटे सिंचाई कार्यों पर अधिक राशि व्यय करनी पड़ेगी । इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि इस प्रयोजन के लिये मन्जूर किया गया धन ऐसी योजनाओं पर लगाया जाये जिनसे जल्दी तथा अधिक लाभ मिले । मेरा निवेदन है कि इस बारे में दक्षिण भारत को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और वहां पर छोटे सिंचाई कार्यों पर अधिक राशि व्यय की जानी चाहिये क्योंकि वहां पर साल में दो या तीन फसलें उगाई जाती हैं ।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : Mr. Speaker, Sir, the most backward area in the whole world is Asian continent, in Asia it is India, in India it is U. P., in U. P. it is the Eastern part and in the Eastern U. P. it is Gorakhpur and the backward class of that area elected me to represent them. The condition in Bihar and U. P. are similar. I will requet the hon. Minister to give irrigation facilities in U. P. similar to that in Bihar.

In our country total area of cultivable land is 42 crore acres, out of which only 34 acres is under cultivation. As regards the Fourth Plan even after its completion only $1\frac{1}{3}$ i. e. 11 crore acres of land will be covered by irrigation. Thus the claim by Government to achieve self-sufficieancy by 19-7071 does not appear to be practicable. When Peking Government is diverting its increasing population military enterprises our Government is launching the sterilization programmes. I will submit that it is better to die fighting than to die of hunger. Our Five Year Plans are aimed at turning Delhi into New YorkBombay into washinton and so on.They are not villageoriented. Is Bombay a backward area,where rural university has been set up ? It should have been established either at U. P. or at Bihar.

Uttar Pradesh has got a rough deal at the hands of the central in the matter of assistance for power development during the three Plans. Even after an outlay of Rs. 157 crores on power projects during the Third Plan and increase in the rated capacity of power generation from 370 m. w. to 910 mw., the consumption of electricity in U. P. is the lowest percapita cousumption of electricity in U. P. is 34 units as compared to 201 in Delhi, 108 in west Bengal, 100 units in Punjab and so on. The existing requirement of bulk consumers of power, such as Fertiliser Factory, Gorakhpur, Heavy Electricals Factory, Hardwar, Antibiotics Factory, Rishikesh, Heavy Fabrication. Naini, Frrtiliser Factory, Kanpur is abtout 400 m.w. and during the Fourth Plan other big industries would be coming up raising the total power requirement to 704 m. g. Since U. P- is a backward State its requirements should be attended to.

Shri Satya Narian Singh (Varanasi) : The present food crisis has not developed suddenly. In fact it is the out-come of the wrong policies constantlypursued by our Government for the last 20 years. Due attention was not paid to the farmers, who are the backbone of the country. Farmers are gradually losing ownership of the land and a new class has emerged who has established its hold on the land. This is a salaried class who does not derive this income from land and therefore the land is not being properly utilised. I will appeal the hon. Minister to take away the land from this class and distribute it among the landless, who may help increase the production and solve the food problem.

Secondly, the farmers have been neglected in all the plans. The farmers constitute 80 per cent of the total population. It should be endeavour to obtain the active participation and cooperation of this section. No Plan can be successful without public cooperation. A national blan should be drawn keeping this aspect in view to solve the food problem The seed and irrigated facilieites provided by the Government do not reach the farmers. The Government should look into it so that these may be fully utilised. The procurement system is faulty and there is no proper distribution of foodgrains. Procurement of foodgrains should be enforced on a countrywide scale and corruption should be rooted but in the distribution system. Then only we will be able to solve the food problem.

श्री काशीनाथ पाण्डे (पदरौना) : में चीनी उद्योग के बारे में कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस उद्योग में 200 कारखाने हैं और 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं। 1965-66 और 1966-67 के तुलनात्मक आंकडे देखने से पता चलेगा कि स्थिति कितनी गंभीर है। चीनी का सीजन 1965-66 में पश्चिम बंगाल में 207 दिन रहा था जब कि 1966-67 में केवल 73 दिन रहा और इसी तरह उत्तरी बिहार में 151 दिन के स्थान पर 52 दिन रहा। चीनी का उतपादन भी इस प्रकार 35 लाख मीट्रिक टन से घटकर 32 लाख मीट्रिक टन रह गया

मुझे चिन्ता इस बात की है कि अगले वर्ण क्या स्थिति होगी। गत वर्ष चीनी कारखानों को गन्ना कम मिलने के कारण उत्पादन कम हुआ क्योंकि चीनी का मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित है जब कि खाण्डसारी और गुड़ उत्पादकों ने गन्ने का अधिक मूल्य दिया। चीनी कारखाने यदि गन्ने का अधिक मूल्य दें, तो चीनी का मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। आपने गन्ने का मूल्य, 2.12 रुपए प्रति मन नियत कर रखा है जबकि ईस वर्ष खाण्डसारी उद्योग ने 6 रुपये प्रति मन तक मूल्य दिया है। इस परिस्थिति में परिणाम यह होगा कि कारखाने बन्द होंगे, मजदूर बेरोजगार होंगे। चीनी के आयात पर हम दुर्लभ विदेशी मुद्रा खर्च नहीं कर सकते। यह मांग की गई है कि गन्ने का मूल्य 4 रुपए प्रतिमन नियत किया जाना चाहिए। लेकिन इससे मूंगफली तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि चीनी पर से नियंत्रण हटा लिया जाये ताकि चीनी कारखाने ज्यादा गन्ना खरीद सकें।

Shri Bramhanandji (Hamirpur) : Mr. Speaker, Sir, we are discussing agriculture but nobody has laid stress on the bollocks and the cow, without whom agricul ture is not possible. We must realise the necessity of cow protection, People here deliver speeches without any practible personal experience of labour in the fields. Unless everyone of us takes to labour produnction of foodgrains will not incerease.

If the rivers are properly honnessed our Bundelkhand can provide enough food for 20 districts, God has bestowed everything on us; our land is not lacking in any respect but it is gone in the hands of capitalist from the tillers. Farmers. lahourers and harijans who soil all the twenty four hours, do not get sufficient remuneration to make their both end meet. They should all be freed from the capitalistic yoke.

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandi Chowk) : Mr. Speaker, Sir, before making any suggestions for the consideration of the Agriculture Ministry. I want to know the reasons for the discontinuance of rice in ration in Delhi. In Kashmir people are being supplied rice at the rate of 6 as. per kilogram whereas in Delhi people have to pay 90 paise for a kilo of rice. Why there is this discrimination ?

Had the amount spent on the Five Year Plans during the last 20 years, been spent on agriculture, we would have not faced the food crisis. large funds Were wasted on housing construction of memorials of departed leaders and I Understand that plans for more such memorials are afoot in Delhi. While on other hand people are being converted by offering the 5 seers of rice.

Ours is an agricultural economy, a village economy but still cow slaugher goes on in the country. The cow wealth has gone down from 15.90 crores in 1955 to 13 crores including uneconomic cows. Prices have reached to a new high in the country. We do not have sufficient food still we are producing tobaco. Growing of tabacoo should be banned till the country attains self-sufficiency in food.

The price of ghee was very low-12. as per maund during the reign of Chandra Gupata Mauraya and 10½ srs for re. 1. during the rurle of Aurangzele-as there was a ban on cow slaughter even by Mughal Emperors such as Akbar, Humayin, Mohamed Tuglaq etc. We can get valuable mineral from cowdung, There should be a ban on use of cowdung as fuel. If cow slaugher is banned in the country milk, ghee and food will be plentiful.

श्री सोना वने (पेंढरपुर) : केवल महन्त और साधुओं को बुलाना चाहिये, वे उत्पादन बढ़ायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि वे भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं ।

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : The mere slogan of socialism is not going to help him. Since we have started following the western countries, our food production has gone down. We require 10½ crore bullocks to plough over 42 crors acres of land. At present we fall short of $3\frac{1}{4}$ crores bullocks. No amount of tractors can serve the purpose of our farmers with small holdings. Bullocks are the only answer. We are exporting hides skins and shoes for earning exchange which results in cow slaughter. Thus our national wealth-cows and bullocks is declining fast. Cow slaughter should be immediately banned in the wider interest of agriculture and the country.

Then, there should be centers after every three miles for supply of seeds to farmers at fair prices. As regards electricity, industrialists get it at rate of 5 paisa per unit whereas a farmer is charged at the rate of 20 and 25 paise per unit. How can thus the prodction increase ? Farmers should be supplied electricity at cheap retes. In case of procurement, the farmer is paid from Rs. 80 to Rs. 100 per quintal when the market price is Rs.

150.-Rs. 160. Farmers should be given adequate irrigation, electricity facilities and a fair price for his produce.

In other countries measures are being taken to increase their population but we are laying too much stress on family planning. Dr. Kothari called it very unfortunate after his recent visit to foreign countries. It will result in foreign dominance. Family planning measures should be given up totally.

I want to make one point about Uttar Pradesh that it has been neglected in the matter of financial assistance fearing that since the Prime Minister belonged to that State, he may not be charged of favouritism. U. P. should no more be neglected and should be treated at par with other States. I support the demands but urge a ban on cow slaughter during the minister-ship of Jagjiwan Ramji.

Shri Latafat Ali Khan (Mazaffarnagar) : Mr. Speaker, Sir, the drought during the last two year is not only factor responsible for the present difficult food situation but the wrong policies pursued by Government during the last 20 years have been primarily responsible for it.

The agriculture has not received its due attention. Only half of the amount allotted for the farmers reaches them because of the corruption in our bureaucratic administrative set up, which are 50 years old. When there was British rule here. The farmers do not get imporved seed and water for irrigation in suficient quaintity and at the appropriate time A large quantity of our foodgrains is destroyed by rodents. Government should conduct some research to control rodents so that huge wastage of foodgrains may be stopped.

अध्यक्ष महोदय : इन मांगों पर कांग्रेस तथा विरोधी पक्ष के सदस्यों को लगभग बराबर समय दिया गया है । कांग्रेस के लगभग 15 और विरोधी पक्ष के लगभग 17 सदस्य बोल चुके हैं । अब भी कांग्रेस के 15-20 सदस्य इन मांगों पर बोलना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि कांग्रेस दल के लिये नियत समय में से 50 प्रतिशत समय मंत्रिगण ले लेते हैं । स्वतन्त्र पार्टी अथवा जनसंघ अथवा कोई अन्य दल तो इसे पूरा कर नहीं कर सकता । एक सदस्य ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी सदस्य को नहीं बुलाया गया । मेरे लिये यह जानना बहुत कठिन है कि कौन सदस्य किस राज्य का है ।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : The time taken by Minister should not be adjusted agailnst the time of the Congress Party.

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर अपने दल की बैठक में चर्चा कर सकते हैं । श्री सोनावने की इस टिप्पणी से मुझे रोष हुआ कि स्वामी जी अनाज क्या करेंगे । चाहे वे स्वामी जी हों अथवा नहीं वे जनता द्वारा चुनकर इस सभा में भेजे गये हैं । किसी के भी मन में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि इस दल अथवा उस दल के साथ भेदभाव किया गया है ।

श्री दाना० तिवारी (गोपालगंज) : मंत्रियों द्वारा उत्तर का समय काग्रेस दल के समय में से नहीं काटा जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार कर सकते हैं, वहां पर अन्य दलों के प्रतिनिधि भी होंगे ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अध्यक्ष महोदय,मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करता हूं। इनमें से अनेक सुझाव सरकार द्वारा पहले ही क्रियान्वित किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी कृषि उत्पादन नीति के लिये छोटे-बड़े सभी किसानों को उत्साहित करना आवश्यक है ताकि वह देश के समक्ष सभी समस्याओं को हल करने में योगदान कर सकें और भाग ले सके। हमारे यहां पर बड़े किसान बहुत कम हैं और छोटे बहुत ज्यादा तथा उनके पास थोड़ी-थोड़ी सी भूमि है। अब भूमि सुधार का प्रश्न उत्पन्न होता है।

विभिन्न राज्यों में विभन्न परिमाण में भूमि सुधार हुआ है। जब तक किसान का भूमि पर कब्जा स्थायी नहीं होता, वह उसमें अधिक पूंजी नहीं लगायेगा और खेती का अधुनिकीकरण नहीं हो सकेगा। कम से कम इतना किया जाना चाहिए। इस प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी और मैं इस पर अग्रेतर बातचीत जारी रखूंगा। लेकिन सभा यह न भूले कि भूमि और कृषि, दोनों ही राज्य सूचि में है। मैं यह तो नहीं कहता कि पिछले 20 वर्षों में भूमि सुधार के क्षेत्र में करिश्मा हुआ है लेकिन साथ ही यह भी कहूँगा कि इस क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों में काफी प्रगति हुई है। कुछ मूल भूमि-सुधार किये गये हैं – जमींदारी, जागीरदारी, इनामदारी का समाप्त किया जाना, यह इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, लेकिन इस कार्य को पूरा करना है परन्तु इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्य सरकारों को पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेगी। विरोधी दलों के प्रतिनिधि विभिन्न राज्य सरकारों में हैं, उन्हें इस दिशा में कार्य करना चाहिए। **[अन्तर्बाधा]**

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये दूसरी आवश्यक चीज है पानी। बिना पानी के बढ़िया से बढ़िया बीज और उर्वरक के प्रयोग से भी कोई परिणाम नहीं निकल सकता। कृषि उत्पादन की किसी भी नीति में सिंचाई, चाहे बड़ी अथवा मध्यम अथवा लघुहो, की ओर सबसे पहले ध्यान देना होगा। मैं स्पष्ट रूपसे मानता हूं कि माध्यम अथवा लघु अथवा छोटी सिंचाई परियोजनाएं काफी नहीं हैं। सिंचाई परियोजनाओंको शीघ्र पूरा करना होगा। प्रयत्न यह होना चाहिए कि बड़ी योजनाओं को नियत समय में पूरा किया जाये तथा यदि संभव हो तो नियत समय से पहले ही पूरा कर लिया जाये। छोटी सिंचाई योजनायें अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनका फल शीघ्र मिलता है और पूंजी पर कम लगानी पड़ती है। लेकिन तीनों प्रकार की सिंचाई योजनाएं क्रियान्वित करनी होगी तथा उनके लिये पूंजी जुटानी होगी।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कही गई इस बात को मैं भी कहना चाहता हूं कि ऋण उपलब्ध होने के मामले में सरकारें अथवा अन्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं से कृषि के साथ वह व्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि उद्योगों के साथ किया गया है। यदि देश को कृषि उत्पादों में आत्म-निर्भर बनाना है और एक सुदृढ़ आर्थिक आधार बनाना है, तो कृषि की ओर पहले की अपेक्षा अधिक ध्यान देना होगा। वाणिज्यिक बैंकों और सरकार द्वारा खेती के लिये वित्त प्रदान करने के मामले में यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी पूंजी अथवा ऋण दिया जावे, वह सुरक्षित रहना चाहिए। उसके डूबने की आशंका न हो। यदि

हम वाणिज्यिक बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं पर प्रभुत्व रखने वाले लोगों में जागृति उत्पन्न कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि छोटी सिंचाई अथवा कृषि सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिये अधिक ऋण मिल सकेगा। लघु सिंचाई कार्यों के लिये अधिक राशि का नियतन करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिये हम अधिक धन देने की स्थिति में हो सकें, इसी कारण से मैंने वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का उल्लेख किया।

पंजाब से आने वाली दो महिला सदस्याओं ने कहा कि लाभकर जोत होनी चाहिए। किसी जोत का लाभकर होने खेती के ढांचे पर निर्भर करता है, न कि खेत के क्षेत्रफल पर। यदि अधिक उपज वाली किस्मों की और गहन खेती की जाती है और साल में तीन फसलें बोई जाती है, तो 5 एकड़ भी लाभकर जोत हो सकती है। इसके विपरीत सुविधाएं न हों, तो 50 एकड़ का खेत भी लाभकर जोत नहीं हो सकता। इसलिये यह नहीं भूलना चाहिए।

यह कहा गया कि पंजाब में खेतिहर मजदूरों को भूमि दी गई, जो वे बेचकर चल गये। इस आधार पर यह दष्टिकोण अपनाना कि उन्हें भूमि न दी जाये, बहुत गलत हैं और इससे हमारी भूमि व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। देश के कुछ भागों में इस कारण से उपद्रव भी हुए हैं। यदि भूमि का वितरण युक्तियुक्त आधार पर नहीं किया जाता, तो हमारे देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो जायेगी।

किसान को ऋण तो देना ही होगा परन्तु सरकार सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण दे अथवा तकावी के रूप में किसान को सीधे ऋण दे, इस पर विचार करना है। अन्त में एक ऐसा तरीका निकालना होगा, जो सबसे अधिक कारगर हो, जिसमें परेशानी भी कम हो तथा ऋण प्राप्त करने में समय भी कम लगे और किसान यह अनुभव करे कि उसे जो भी सहायता मिलनी चाहिए, वह उत्तरोत्तर मिल रही है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके सफल हो सकते हैं। इस पर विचार करना होगा।

यदि सहकारिता आन्दोलन में कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं, तो राज्य सरकारों को उन्हें दूर करना है। देश के सब भागों में तो नहीं परन्तु कुछ भागों में सहकारी संस्थाओं के काम के बारे में शिकायतें मिली हैं और कुछ में सचाई भी है। सहकारिता आन्दोलन की इस कारण से निन्दा नहीं की जानी चाहिए। बल्कि हमें सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल यह ही एक ऐसी एजेंसी होगी जो वहां की जनता को उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का प्रशासन संभालने के लिये तैयार करेगी। जहां तक त्रुटियों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारें उन्हें दूर करने में सक्षम है।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : क्या वे मन्त्रियों को सलाह देंगे कि कि सहकारी संस्थाओं से थैलियां स्वीकार न करें।

श्री जगजीवन राम : यदि किसी समिति के सदस्य सर्वसम्मति से ऐसा करने का निश्चय करें, तो मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं ? परन्तु इस प्रकार धन खर्च वांछनीय अवश्य नहीं है। किसानों से मांग करते रहे हैं कि उन्हें नकदी की अपेक्षा उर्वरक कृषि उपकरणों, कीटनाशक दवाइयों आदि के रूप में सहायता दी जाये। लेकिन यह तभी संभव है जबकि

किसानों के क्षेत्र में इन सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोई संस्था हो । सहकारी समितियों द्वारा अधिक ब्याज लेने की शिकायतें भी आई हैं और कुछ सच भी हैं । रिजर्व बैंक तो सहकारी समितियों से ब्याज की चालू दर से 2 रुपए प्रति सैकड़ा कम ब्याज लेता है । मूल सरकारी बैंक किसानों से $8\frac{1}{4}$ रुपए प्रति सैकड़ा से कुछ मामलों में $10\frac{1}{2}$ रुपए प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज लेते हैं क्योंकि एपेक्स बैंक, प्रादेशिक बैंक, जिला बैंक और मूल बैंक सभी को थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा देना पड़ता है । मैंने जांच आरम्भ कर दी है कि क्या हम किसानों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की वर्तमान दर में कोई कमी कर सकते हैं ।

श्री क० न० तिवारी (बेतिया) : उद्योगपतियों को किस दर पर ऋण दिया जाता है ।

श्री जगजीवन राम : उन्हें बाजार दर पर वाणिज्यिक तथा अन्य बैंकों से ऋण मिलता है । मैं गलत अनुमान नहीं लगाना चाहता परन्तु मैं समझता हूं कि यह 10 रुपए प्रति सैकड़ा से कम नहीं होगा बल्कि अधिक ही होगा ।

इसके पश्चात लोकसभा मध्यान भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen on the clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बज कर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past Fourteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : आज हम चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में शीघ्र फलदायक उपाय किये जायें । किसानों को पानी देने के लिये हमें सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना होगा, नलकूप, उठाऊ सिंचाई, कुएं, तालाब आदि, किसान को ऋण देना होगा तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को. चाहे इस्पात हो अथवा सीमेंट, पूरा करना होगा । कुछ सदस्यों ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं दिये गये । हमने सावधानी बर्ती है कि राज्यों में अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिलें और हम विशेष प्रयास करेंगे कि अधिक आवश्यकता हो, तो उसे भी पूरा किया जाये । तमिनाड के सदस्यों ने नेवेली कारखाने द्वारा उर्वरकों की बिक्री में अवांछनीयता का उल्लेख किया । मैं इस मामले में जांच करुंगा और दोषों को दूर किया जायेगा । रसायनिक उर्वरकों के साथ-साथ कार्बनिक उर्वरकों की ओर भी हमें ध्यान देना होगा ।

श्री जगजीवन राम : जारी ।

हमारे देश के लिये कृषि कोई नई चीज नहीं है । मैं इस पर फिर जोर देना चाहूंगा कि भारतीय किसान चाहे अशिक्षित हो, परन्तु वह अपना कर्तव्य इतनी अच्छी तरह से जानता है कि वह उन्हें परामर्श दे सकता है जिन्होंने कृषि कालिजों में शिक्षा प्राप्त की हैं, परन्तु जिन्हें अनुभव नहीं है । हमारे किसान रूढ़िवादी नहीं हैं, परन्तु इसमें शक नहीं कि वह सतर्क हैं ।

वह सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखता । यदि वह कोई ऐसा व्यवहारिक प्रदर्शन देखता है जिससे वह सन्तुष्ट हो जाता है कि इससे उसकी उपज में वृद्धि होगी तो वह उस प्रक्रिया को न अपनाने पर जोर नहीं देता । यदि वह पड़ौसी किसान को ऐसे आधुनिक तरीके अपनाते देखता है जिनसे उपज बढ़ सकती है जो वह उन्हें शीघ्रता से प्रयोग करता है ।

कार्बनिक खाद के प्रयोग करने पर भी पूरा जोर देना होगा । में चाहूंगा कि सरकार कुछ ऐसी कार्यवाही को जिससे खादें उत्पन्न करने के लिये किसानों को प्रोत्साहन दिया जाये । हमें अपने किसानों के लिये उपक्रमों की व्यवस्था करनी होगी; मेरा अभिप्राय आधुनिक उपक्रमों से है । आंठ या नौ जिलों में सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि सम्बन्धी औजार बनाने के के लिये सरकार की एक योजना है । मैं यह चाहता हूं कि यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्रता से किया जाये । ट्रैक्टरों की भी बहुत मांग है । कुछ ही किसान इसको खरीदने और रखने में समर्थ हैं । यदि भारतीय कृषि को चलाना है तो छोटे किसानों के लिये भी इस सुविधा की व्यवस्था करनी पड़ेगी । मैंने अपने मन्त्रालय से ऐसी योजना बनाने के लिये कहा है जिसके परिणामस्वरूप छोटे किसानों को भी ट्रैक्टर उपलब्ध हो सकें । केन्द्र को सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित करना चाहते हैं जहां से किसान नियत दरों पर ट्रैक्टर किराये पर ले सकें । ये केन्द्र केन्द्रीय सरकार, सहकारी समितियां या गैर सरकारी दल भी चला सकते हैं यही बात सिंचाई के लिये प्रयोग किये जाने वाले ट्यूबवेलों पर भी लागू होती है ।

कृषि के सम्बन्ध में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय यह ध्यान देना आवश्यक हैं कि उससे न केवल बड़े किसानों बल्कि छोटे किसानों को भी लाभ पहुंचे ।

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से भी लाभ उठाना पड़ेगा । हमने सभी राज्य सरकारों को पहले ही सलाह दी है कि कम से कम प्रत्येक राज्य में एक कृषि कालिज खोला जाना चाहिये और उसके लिये हम राज्यों को पूरी तरह से सहायता देने को तैयार हैं। गवेषणा और प्रयोगों की बड़ी आवश्यकता है । गवेषणा को न केवल वैज्ञानिक क्षेत्रों तक सीमित रखना है बल्कि इसके परिणामों को खेतों तक पहुँचाना होगा और इस समय हम ऐसा ही कर रहे हैं । हमने एक विस्तार सेवा चालू की है ।

हमें केवल उन्हीं को प्रशिक्षण नहीं देना है जो विश्वविद्यालयों या कालिजों से आये हैं बल्कि हमें किसानों को भी प्रशिक्षण देना है । हम प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि इसका और विस्तार किया जाये । मिट्टी का कटाव हमारी कृषि में बहुत रुकावट डालता है । उसको रोकने के लिये हमें यथा सम्भव प्रयत्न करने होगे । इस सम्बन्ध में वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं । अतः यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर वृक्ष उगाये जाये ।

आधुनिक विज्ञान के अलावा हमें अपनी पुराने प्रचलित तरीकों पर भी ध्यान देना है । हमें पुराने और आधुनिक तरीकों को मिला कर पूरा पूरा लाभ उठाना है ।

किसानों को उनके द्वारा किये गये उत्पादन पर उचित लाभ दिये जाने का आश्वासन दिया जाना चाहिये । उद्योग के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी कृषि की वस्तुओं के मूल्य निर्धा-

रण करते समय उत्पादन लागत पर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसको काफी पहले निर्धारित किया जाना चाहिये ताकि किसान को पहले ही यह पता लग जाय कि उसे उसके उत्पादन का क्या मूल्य मिलेगा।

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : You have formulated Agriculture Commission, but the agriculturists are not getting the remunerative prices which they ought to get. They are very conservative people. Wh ether you inted to appoint some farmers also in this Commission ?

श्री जगजीवन राम : कृषि मूल्य आयोग अपनी सिफारिशें देता है, परन्तु जब सरकार यह सोचती है कि कृषि मूल्य आयोग किसानों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगा तब सरकार ने उन सिफारिशों को किसानों के लाभ में परिवर्तित करने में कोई हिचक नहीं की। हमने फसल बीमा की योजना अपनाई है। विधेयक का मसौदा तैयार हो रहा है। हम राज्य सरकारों से सलाह कर रहे हैं और इस विधेयक को पास करने का अवसर लिया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य नीति के बारे में कई सुझाव प्राप्त हुए हैं।

जहां तक खाद्य के प्रबन्ध किये जाने का सम्बन्ध है खाद्य का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि खाद्य कमी वाले क्षेत्रों में उचित मूल्य पर उपलब्ध हो।

यह कहा जाता है कि जब अनाज उपलब्ध होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अनाज के दाम केवल अनाज की उपलब्धि या अनोपलब्धि पर ही निर्भर नही करते। अनाज के मूल्यों पर कई आर्थिक बातों का प्रभाव पड़ता जो किसी विशेष समय मौजूद होती हैं। उन पर भी विचार करना होता है।

खाद्य विभाग बनाये रखने का प्रयोजन यह है कि देश के कमी वाले क्षेत्रों में अधिक मात्रा में अनाज प्राप्त हो सके और अधिक अन्न उत्पन्न करने वाले क्षेत्र कम अनाज पैदा करने वाले क्षेत्रों की यथा सम्भव सहायता कर सके। अधिक अनाज उत्पन्न करने वालों की सहायता और देश में उत्पन्न होने वाले अनाज को मिलाकर भी देश की अनाज की आवश्यकता पूरी नहीं होती। अतः हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

ऐसे सुझाव दिये गये हैं कि यदि हम खाद्य क्षेत्रों को समाप्त कर दें तो सब ठीक हो जायेगा। खाद्य और कृषि मुख्यतः राज्य सरकार का दायित्व है। खाद्य और कृषि के सम्बन्ध में हम जो भी करते हैं वह राज्य सरकारों की स्वीकृति से करते हैं। वर्तमान खाद्य क्षेत्रों की सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की सर्व सम्मति से की गई हैं। सभा में कुछ ऐसी भावना उत्पन्न हो गई है कि कमी वाले सभी राज्य खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करना चाहते हैं। यह सच नहीं है। मुख्यमन्त्री सम्मेलन में केवल दो मुख्य मन्त्रियों ने खाद्य क्षेत्र समाप्त करने के विचार का समर्थन किया था और दूसरे कमी वाले राज्य और अधिक अनाज उत्पन्न करने वाले राज्य इन दोनों को बनाये रखने के पक्ष में थे।

खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध हटाने के सम्बन्ध में हमें जो भी नीति निर्धारित करनी पड़ती है वह कमी और अधिक अन्न उत्पादित राज्यों

के मुख्य मन्त्रियों की सलाह से की जाती है। किसान अबाद मंडी चाहता है ताकि वह अधिकतम मूल्य पर अनाज बेच सके। सभा को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये कि देश क्या करने में समर्थ है। यह मद्रास, कलकत्ता और बम्बई को राजकीय सहायता के रूप में अनाज सप्लाई करने का प्रश्न नहीं है। यदि यह ऐसा है तो सब राज्य सरकारें अपने नागरिकों को खाद्यान्न सप्लाई कर सहायता क्यों नहीं करती। जो भी मात्रा में खाद्यान्न पंजाब से उपलब्ध हो रहे हैं पंजाब सरकार उसको प्राप्त कर रही है। यदि पंजाब सरकार ऐसा नहीं कर सकेगी तो केन्द्र जरूरत से अधिक अनाज पंजाब से ले लेगा।

राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था। मैं पहले भी बहुत से अवसरों पर कह चूका हूं कि यदि कोई राज्य सरकार अनाज का राज्यकीय व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहती हैं तो केन्द्रीय सरकार अनाज की खरीद के लिए सभी प्रकार की वित्तीय सहायता देगी।

कुछ राज्यों को कम मात्रा में अनाज दिए जाने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है। हमारे पास अनाज की कमी है। हमें आयातित अनाज पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि ऐसा होता है तो वह सब राज्यों के साथ होता है।

कांग्रेस और गैर--कांग्रेस सरकारों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये हैं। प्रत्येक का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह अनाज समस्या को राजनीति से अलग रखे। वास्तव में देखा जाये तो अनाज की मात्रा का अधिक भाग विभिन्न गैर-सरकारों को सप्लाई किया जा रहा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अनाज की सप्लाई करते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते कि क्या वह कांग्रेसी या गैर-कांग्रेसी सरकार है क्योंकि जनता तो अनाज चाहती है।

दिल्ली देश की राजधानी है और यहां होने वाली घटनाओं का देश में असर होता है। देश में चावल की कमी है। दिल्ली चावल खाने वालों का क्षेत्र नहीं है। मैंने ऐसा किया है कि जो लोग चावल नहीं खाते उनको दिया जाने वाला एक किलो चावल अस्थाई तौर से बन्द कर दिया गया है। यह केवल एक या दो महिने के लिए है। चावल की स्थिति में सुधार हो जाने पर वह फिर उपलब्ध होने लगेगा।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष चीनी का उत्पादन बहुत कम है। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पड़े भंयकर सूखे की सभा को जानकारी है। इससे हमारी चीनी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। पिछले वर्ष चीनी का उत्पादन 35लाख टन था। इस वर्ष लगभग इसका उत्पादन 2 लाख टन हुआ है। अतः हमें विभिन्न राज्यों को दिया जाने वाला कोटा उसी अनुपात में करना पड़ता था। यदि राज्य सरकारें वितरण का प्रबन्ध उचित ढंग से कर लेती हैं तो कीमतों में कोई वृद्धि होने का प्रश्न नहीं उठता।

इस समय चीनी की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से खाद्य समस्या का हल करना चीनी समस्या के हल करने से आसान है, यद्यपि खाद्य समस्या भी जटिल है। इस समय हम चीनी की नीति के सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं। अगले 10 या 15 वर्षों के दौरान हम चीनी नीति के सबंन्ध में कुछ निर्णय लेने में समर्थ हो जाएंगे।

कटौती प्रस्तावों पर मतदान हुआ और अस्वीकृत हुए

The Cut motions were put and nagatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

The Following Demand in respct of Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
32	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	99,29,000
33	कृषि	6,17,89,000
34	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को अदायगियां .	11,00,39,000
35	सामुदायिक विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा	7,60,000
36	वन	1,07,63,000
37	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	25,60,04,000
121	अन्न तथा उर्वरक की खरीद . .	4,76,61,76,000
122	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . . .	21,10,59,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1967-68 के लिए खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
32	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	99,29,000 रु०
33	कृषि	6,17,89,000 रु०
34	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां ,	11,00,39,000 रु०
35	सामुदायिक विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा	7,60,000 रु०

36	वन	1,07,63,000 रु०
37	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	25,60,04,000 रु०
121	अन्न तथा उर्वरक की खरीद . . .	4,76,61,76,000 रु०
122	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	21,10,59,000 रु०

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 15 और 16 पर चर्चा तथा मतदान होगा ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

वर्ष 1967-68 के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
15	वैदेशिक-कार्य	11,05,93,000 रु०
16	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	10,94,70,000 रु०

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 62 से 68 का समर्थन करता हूं । मैं यह समझता हूं कि यह कहना सही है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से लेकर आज तक भारत सरकार की विदेशी नीतियों तथा देश की जनता की राय में इतना बड़ा मतभेद कभी नहीं हुआ चाहे यह मतभेद पश्चिम एशिया सम्बन्धी विदेश नीति से सम्बन्ध रखता हो या पेकिंग सरकार के साथ बर्ताव से या तिब्बत की जनता के अधिकारों से । इसका कारण यह है कि भारत सरकार अभी भी उन नीतियों का अनुसरण कर रही है जो 20 वर्ष पहले सर्वथा भिन्न परिस्थितियों में निर्धारित की गई थी जब कि संसार की स्थिति में अब आमूल परिवर्तन आ चुका है ।

दो मुख्य घटनाओं के कारण संसार आज बदला हुआ है । पहली घटना साम्यवादी चीन का आणविक राष्ट्र के रूप में प्रकट होना है जिससे हमारे देश की स्वतन्त्रता को प्रत्यक्ष रूप से खतरा हो गया है । यद्यपि यह खतरा मुख्य रूप से राजनीतिक हैं जिसका उदाहरण हमें नकसलबाड़ी में साम्यवादी अड्डे की स्थापना से मिलता है फिर भी साम्यवादी चीन एक ओर पाकिस्तान को उकसा कर भारत को घेरने का प्रयत्न कर रहा है और दूसरी ओर वियतनाम की घटनाओं के माध्यम से वह सिंगापुर तक आ जाने की धमकी दे रहा है । दूसरी नवीन घटना अमरीका और रूस के बीच सम्बन्धों में परिवर्तन की है । इन दो महान राष्ट्रों के बीच अब

किसी प्रकार का झगड़ा या किसी प्रकार का शीत युद्ध नहीं चल रहा है जैसा कि भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय चल रहा था निश्चय ही उनके सम्बन्धों में परिवर्तन हुआ है और रूसी प्रसारवाद को, जो युद्ध कुछ वर्षों से चल रहा था, रोक दिया गया है। जब भी प्रसारवाद ने सर उठाने की कोशिश की है. जैसा कि बर्लिन में या क्यूबा में, इसको दृढ़ता से दबा दिया गया है। इस नये संदर्भ में भारत को ऐसा काम करना चाहिये जिससे हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो और दो महान् राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय संकट की स्थिति में आपस में अधिक सहयोग कर सकें जैसा कि समय समय पर करते रहे हैं।

भारत बड़ी सुगमता से दो महान राष्ट्रों तथा एशिया के छोटे देशों में विशेपकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच मध्यस्थ का काम भली भांति कर सकता है। यह स्पष्ट है कि यदि भारत दो महान राष्ट्रों में से एक के साथ खुले आम मिल जाता है या उनके आपस में सहमत होने पर उन दोनों के विरूद्ध कार्य करता है तो वह इस प्रकार का काम नहीं कर सकता। इसलिये भारत जहां इन दो राष्ट्रों में सहयोग की संभावना समझे वहां भारत को अपना नैतिक समर्थन प्रदान करना चाहिये और जहां उनके आपसी संघर्ष की संभवना हो वहां किसी भी पक्ष का समर्थन करने से इन्कार कर दें। दुर्भाग्य से सरकार की वर्तमान नीतियों के होते हुए ऐसा कार्य करना सम्भव नहीं है।

हमें चीन की परमाणु शक्ति से खतरा है। परन्तु अब परमाणु शस्त्रों को बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि चीन ने हाइड्रोजन बम का विस्फोट करके भारत में पलूटोनियम पर आधारित विकास की बात को एक दम पिछड़ा बना दिया है। परमाणु बम की लागत को सहन करना भी हमारे लिये कठिन है। यदि फ्रांस के बजट का उदाहरण दिया जाए तो पता चलेगा कि इस कार्य के लिये भारत को प्रत्येक वर्ष 3,2000 करोड़ रु० खर्च करने पड़ेंगे। यह राशि चौथी योजना के कुल परिव्यय से भी अधिक है। बजाये इसके कि हम ऐसी नीति अपनायें जिससे दोनों महान राष्ट्र नाराज न हो जिनकी हमें साम्यवादी चीन के खतरे के विरूद्ध सहायता की आवश्यकता है, भारत को परमाणु शस्त्रों के प्रसार की रोक संधि पर इस शर्त पर हस्ताक्षर करने चाहिये कि दोनों राष्ट्र इस सम्बन्ध में संयुक्त रूप में तथा प्रथक रूप में साफ साफ गारंटी देंगे। मास्को और वाशिंगटन में सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। परन्तु सरकार ने आवश्यक गारन्टी प्राप्त करने के लिए इस स्थिति से लाभ नहीं उठाया है।

जहां तक पश्चिम एशिया का सम्बन्ध है, हमारे दल की नीति यह है कि इसरायल और अरब देशों अर्थात्, दोनों के साथ मित्रता रखी जाये और उनके विवाद के सम्बन्ध में हम तटस्थ एवं निरपेक्ष बने रहें। मेरे दल तथा अन्य विरोधी दलों ने 5 जून को प्रधान मन्त्री ने लिखा था कि इस सम्बन्ध में निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाये और इस अवस्था में किसी पर आरोप न लगाये जाये और न ही किसी का पक्ष लिया जाए। हमने यह भी अपील की थी कि भारत सरकार को टर्की, ईरान, मलेशिया आदि की तरह तटस्था को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाना चाहिये।

यह कहना सही नहीं है कि इसरायल ने आक्रमण किया है। सचाई इसके विपरीत ही है। राष्ट्रपति नासिर ने कहा था कि ईसरायल का अस्तित्व मिटा दिया जायेगा और यह कि

वह इसराइल के साथ किसी प्रकार का सह-अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा था कि अरब देशों और इसरायल के बीच वर्ष 1948 से युद्ध की स्थिति चल रही है। राष्ट्रपति नासिर ने गाजा से संयुक्त राष्ट्र संघ की आपतकालीन सेना को हटाने के बाद 24 मई को अकावा की खाड़ी को बन्द कर दिया गया और यही युद्ध वाली कार्यवाही थी। इसरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने से इन्कार करने के कारण भारत सरकार को काफी नुकसान उठाना पडा है। अरब देशों की मित्रता खोये बिना ही 87 देशों ने इसरायल और अरब देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए हैं। हमारी एक-पक्षीय जानकारी के कारण संसार की दृष्टि में हमारी सरकार की स्थिति हास्यास्पद बन गई हैं। इसरायल को वर्तमान स्थिति में सेना हटाने के लिए कहना तब तक उपहासजनक होगा जब तक कि संयुक्त अरब गणराज्य सीरिया तथा अलजीरिया उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर लेते जो बदला लेने के लिये युद्ध का खुले आम प्रचार कर रहे हैं और इसरायल के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। जब तक इस प्रकार का रवैया छोड़ दिया नहीं जाता तब तक इसराइल को पीछे हटने के लिए कहने का कोई अर्थ नहीं है।

प्रो० आरनोल्ड टयन्बी अरब देशों के एक प्रसिद्ध मित्र है। उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए जो सुझाव दिये हैं वे अच्छे है। ये सुझाव इस प्रकार है :—(एक) अरब देशों को इसरायल के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना चाहिए ; (दो) पैलेस्टाइन के शरणार्थियों की समस्या का समाधान करने के लिए इसरायल को तैयार हो जाना चाहिए ; (तीन) मार्ग के परस्पर अधिकार दिए जांए ; इसरायल नहर स्वेज तथा टिरान के जल डमरु में स्वतन्त्र रुप से जहाज चला सकेगा और जार्डन हायफा और जाफा के पतनों तक जा सकेगा ; (चार) अन्तर्राष्ट्रीय प्रन्यासिता के अधीन जेरुसलम के पवित्र नगर को स्वतन्त्र नगर घोषित किया जाए। मैं समझता हूँ कि बातचीत आरम्भ करने के लिए यह एक अच्छा आधार है।

श्री सन्त बक्स सिंह (फतेहपुर) : मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ। पश्चिमी एशिया के प्रश्न पर देश में बड़ी हलचल है। जनता के समक्ष गलत ढंग से मामला पेश किये जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसी स्थिति में जबकि इसरायल ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने ही पहले लड़ाई शुरु की है यह कहना निरर्थक है कि इसरायल आक्रमक नहीं है। वास्तव में बड़े राष्ट्र इसरायल को अन्य विकसित लोगों का दमन करने के लिये उकसा रहे हैं। हम अरब लोगों के साथ हैं क्योंकि उनका पक्ष न्याय का है और वे बड़े राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहे हैं।

यह कहना सही नहीं है कि पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में हम गुट-निरपेक्षता की नीति को छोड़ रहे हैं। पंडित नेहरू ने स्वयं स्पष्ट किया था कि आक्रमण और अन्याय की स्थिति में हम न तटस्थ रह सकते हैं और न रहेंगे। अरब देशों के साथ मित्रता बनाये रखना हमारे हित में है। उन देशों के साथ हमारा करोड़ों रुपये का व्यापार होता है। यह हमारे हित में है कि हम अरब जगत के प्रगतिशील तत्वों का साथ दें और उनको एक मुस्लिम शक्ति कह कर मामले को न उलझाएं। लेबनान में एक ईसाई राष्ट्रपति है। एक व्यक्ति के धर्म से कोई अन्तर नहीं पड़ता।

पंडित नेहरू ने स्वयं कहा था कि राष्ट्रपति नासिर ने कोलम्बो प्रस्तावों के समय तथा कासाबलांका में हमारे विरुद्ध निन्दा के प्रस्ताव को पास न होने देने में हमारी बहुत सहायता की थी।

यह कहना भी बेकार है कि हम अकेले तथा अलग पड़ गये हैं। बाण्डुंग, बैलग्रेड और गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के द्वितीय सम्मेलन में पास हुए संकल्पों से पता जलता है कि 52 राष्ट्र हमारे साथ हैं। हमें छोटे-छोटे राष्ट्रों के साथ, जिसकी समस्याएं हमसे मिलती-जुलती हैं, सम्बन्ध बढ़ाने चाहिये। इसरायल के साथ राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने की अपेक्षा ऐसा करना अधिक लाभदायक है। आर्थिक क्षेत्र में हमें जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए जिसने रसायन तथा कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त प्रश्चात हमने एशिया की दो बड़ी शक्तियों अर्थात रूस और चीन के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का यत्न किया। अक्सर कहा जाता है कि चीन के प्रति हमारी नीति असफल रही है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह देश सब देशों के प्रति ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। बर्मा, इन्डोनेशिया और अफ्रीका में चीन की नीति पूर्णतया असफल रही है। हम चीन के साथ न तो युद्ध की बातें करना चाहते हैं और न ही हम युद्ध-प्रिय देश बनाना चाहते हैं। चीन इतिहास के एक विशेष दौर से गुजर रहा है। हम चीन के साथ वही सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं जो कि गत 2,000 वर्षों से चले आ रहे हैं।

मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि हमें उद्योगों में प्रगतिशील जापान जैसे एशियाई देश के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए।

विदेशों में हमारे राजनीतिज्ञों को साधारण जीवन बिताना चाहिये तथा नम्रता का परिचय देना चाहिए।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 16 से 23 प्रस्तुत कर रहा हूं। कांग्रेस के सदस्यों की ओर से ऐसा कहा गया है कि हमारी विदेश नीति समय की कसौटी पर पूरी उतरी है। परन्तु मेरे विचार में हमारी विदेश नीति पूर्णतया असफल रही है। विदेश नीति की असफलता के कारण ही हमारे देश पर गत बीस वर्षों में चार बार आक्रमण हो चुका है तथा पाँचवें आक्रमण की तैयारी हो रही है।

किसी भी स्वतन्त्र देश की विदेश नीति उस देश के राष्ट्रीय हितों पर ही आधारित होनी चाहिये। वर्तमान परिस्थितियों में विश्व-शान्ति, पंचशील गुट निरपेक्षता आदि महत्वहीन उक्तियों का विदेश नीति में कोई स्थान नहीं है। विदेश नीति एक नीति है न कि सिद्धान्त।

जहां तक गुट-निरपेक्षता की नीति का सम्बन्ध है प्रत्येक देश को गुट-निरपेक्षता तथा गुटों से गठबंधन की नीति अपनानी होती है। जहां तक कि संयुक्त अरब गणराज्य ने भी इराक तथा सीरिया के साथ सैनिक समझौते किये हुए हैं। अतः किसी भी देश की विदेश नीति उसकी भूगोलिक स्थिति तथा पड़ोसी देशों के रवैये तथा सुरक्षा की आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए।

पाकिस्तान और चीन हमारे निकटतम पड़ोसी हैं। पाकिस्तान हमारा जन्मजात शत्रु है और उसका अस्तित्व ही हमारे साथ तनाव बनाये रखने पर निर्भर करता है। यदि पाकिस्तान भारत के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से रहना सीख ले तो उसका अलग राज्य के रूप में अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। अतः पाकिस्तान का कोई भी शासक हो वह भारत के साथ तनाव बनाये रखेगा।

पाकिस्तान के साथ तनाव का कारण काश्मीर नहीं है बल्कि यह तनाव का परिणाम है। यदि हम पाकिस्तान को दस काश्मीर भी दे दें तो भी पाकिस्तान हमारा शत्रु बना रहेगा। यदि हम पाकिस्तान के पिछले 20 वर्ष के इतिहास को देखे तो पता चलेगा कि उन्होंने हमारे प्रति क्रूरता की ही नीति अपनाई है और उससे उन्हें लाभ भी हुआ है। 1948 के आक्रमण में उन्होंने हमारे 40,000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार नहरों के पानी सम्बन्धी समझौते से भी उनको लाभ हुआ। फिर लाठीटीला, दुम्बामारी के दो गांवों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। यही कारण है कि पाकिस्तान आक्रामक रवैया अपनाये हुए है। पाकिस्तान के साथ निपटने के लिए हमें दृढ़ तथा कठोर नीति अपनानी चाहिए।

हम अभी तक ताशकन्द समझौते की बात कर रहे है जबकि पाकिस्तान ने इसको समाप्त कर दिया है। अतः हमें भी पाकिस्तान के प्रति अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना चाहिए। यदि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर दूसरा मोर्चा बना सकता है तो हमें भी पखतुनिस्तान का प्रश्न उठाना चाहिए। हमें इस बारे में पठानों का पूरा समर्थन करना चाहिए।

वास्तव में उत्तर में हमारी सीमाएं चीन के साथ नहीं बल्कि तिब्बत से मिलती हैं। चीन को तिब्बत पर कब्जा करने की अनुमति दे हमने सब से बड़ी गलती की। अब चीन आर्थिक, राजनैतिक तथा सैनिक क्षेत्र में हमारा शत्रु हो गया है। 7 नवम्बर, 1950 को अपने एक पत्र में सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को लिखा था कि चीन हमारे लिए एक बड़ा खतरा सिद्ध होगा और वह न कि केवल तिब्बत बल्कि आसाम तथा बर्मा पर भी अपना प्रभुत्व चाहता है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमें चीन के प्रति एक स्पष्ट तथा दृढ़ नीति अपनानी चाहिए और लोगों को इस भावी खतरे के प्रति जागरूक करना चाहिए। सरदार पटेल का कहा हुआ एक-एक शब्द ठीक सिद्ध हो रहा है। अतः हमें अब भी चीन को अच्छी प्रकार समझना चाहिए तथा उसके प्रति एक यथार्थवादी नीति अपनानी चाहिए। यथार्थवादी नीति यही हो सकती है कि हम तिब्बत की स्वतन्त्रता का समर्थन करें। तिब्बत कभी भी चीन का भाग नहीं रहा। गत 2500 वर्षों से तिब्बत का अपना स्वतन्त्र इतिहास है। वास्तव में तिब्बत के आर्थिक, वाणिज्यक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध सदा से भारत के साथ रहे हैं। चीन के साथ तिब्बत का यदि कोई सम्बन्ध था तो वह मान्चू बादशाहों के कारण था। 1911 में दलाई लामा ने कहा था कि अब जबकि मान्चू बादशाहों का शासन समाप्त हो गया है उनका चीन से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। अतः तिब्बत के प्रति हमने गलत नीति का अनुसरण किया। 1954 के समझौते से तिब्बत पर चीन के प्रभुत्व को स्वीकार कर हमने सब से बड़ी गलती की। चीन ने इस समझौते पर कभी भी अमल नहीं किया। अतः हमें भी इस समझौते को

समाप्त कर देना चाहिए। हमें तिब्बत के मामले को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाना चाहिए। हाल ही में दलाई लामा ने एक वक्तव्य में कहा है कि जब तक तिब्बत स्वतन्त्र नहीं हो जाता तब तक एशिया में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। अतः यदि हम चाहते हैं कि विश्व के इस भाग में शान्ति स्थापित हो तो तिब्बत को स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। हमारी विदेश नीति का भी यह प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। दूसरे हमें चीन के साथ राजनैतिक सम्बन्ध बनाये रखने में कोई लाभ नहीं है। अतः इनको समाप्त किया जाना चाहिए। तीसरे हमें संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश का समर्थन नहीं करना चाहिए। चौथे जिन देशों को चीन से खतरा है हमें उनके साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का यत्न करना चाहिए। हमें नेपाल, बर्मा तथा श्रीलंका के साथ 'बड़े भाई' का नहीं बल्कि समानता का बर्ताव कर उनको अपना मित्र बनाना चाहिए।

पश्चिमी एशिया के बारे में मैं संयुक्त राष्ट्र में दिये गये श्री चागला के भाषण की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जब राष्ट्रपति नासिर इसरायल को समाप्त करने की धमकी दे रहे थे तब उनकी सह-अस्तित्व की नीति कहां थी। यदि हम वास्तव में सह-अस्तित्व की नीति पर चलना चाहते हैं तो पश्चिम एशिया में हमें अपनी नीति को बदलना होगा। जिस प्रकार चीन तथा पाकिस्तान के साथ हमारे संघर्ष में अरब देशों ने गुट-निरपेक्षता की नीति पर अमल किया था ठीक उसी प्रकार हमें भी इसरायल के साथ इनके संघर्ष में गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करना चाहिए। हम नासिर को यह अधिकार नहीं दे सकते कि वह हमारे मित्रों के बारे में निर्णय करें। हम इसरायल तथा संयुक्त अरब गणराज्य दोनों के साथ ही मिलना चाहते हैं। जिस प्रकार नासिर कहते हैं कि वह भारत के अच्छे मित्र हैं परन्तु वह चीन और पाकिस्तान के भी मित्र हैं उसी प्रकार हमें भी उनको बता देना चाहिए कि हम उनके अच्छे मित्र हैं परन्तु हम इसरायल के भी मित्र हैं।

ऐसा कहा गया है कि इसरायल ने हमारे सैनिकों की हत्या की हैं। इस बारे में जांच की जानी चाहिए। तभी पता चलेगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। उनके मारे जाने के लिए इसरायल को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यदि उनके मारे जाने के लिए कोई जिम्मेदार हैं तो वे भारत सरकार, प्रतिरक्षा मंत्री तथा प्रधान मंत्री है। यदि कनाडा अपने 800 सैनिकों को वहां से निकाल सकता हैं तो हम अपने सैनिकों को वहां से क्यों नहीं निकाल सकते थे।

अरब विश्व नाम की कोई वस्तु नहीं है। वहां पर 13 राज्य हैं। हमें प्रत्येक राज्य के साथ द्विपक्षीय आधार पर सम्बन्ध बनाने चाहिए। जार्डन, सीरिया साऊदी अरब ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। अतः मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वे देश हमारे मित्र हैं। हमें उन राज्यों के साथ पारस्परिकता के आधार पर सम्बन्ध बनाने चाहिए।

भारत-अरब लीग के अध्यक्ष देश में शरारत कर रहे हैं। वह भारतीय कानूनों को तोड़ने के लिए अरब विद्यालयों भड़का रहे हैं। इस बात को सहन नहीं किया जा सकता। अतः उसे लीग को दी गई राजनयिक मान्यता वापिस ली जानी चाहिए।

हमें दोनों बड़ी शक्तियों अर्थात् अमरीका तथा रूस के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाने का यत्न करना चाहिए। परन्तु ऐसा करते समय हमें उन पर निर्भर नहीं करना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि भारत एक बड़ी शक्ति बने। अमरीका ने हमारी सहायता की परन्तु अवमूल्यन के रूप में उस सहायता का मूल्य ले लिया। इसी प्रकार रूस ने अपनी सहायता का मूल्य ताशकन्द समझौते के रूप में हम से वसूल कर लिया है। रूस ने समाचार-पत्र तथा रेडियो हमारे आन्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे सर्वश्री मोरारजी देसाई तथा पाटिल की निन्दा कर रहे हैं और साथ-साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा कामराज की प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं श्री मसानी के साथ इस बात में सहमत नहीं हूँ कि हमें अणु बम्बों से आक्रमण से बचाव के लिए गारंटी लेना चाहिए। हमें इस बारे में किसी पर निर्भर न रह कर स्वयं अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए हमारे पास आवश्यक हथियार होने चाहिए।

हमें लेटिन अमरीका, अफ्रीका तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे देश अमरीका तथा रूस के चंगुल से छुटकारा पा रहे हैं। इसके साथ-साथ जिन देशों में भारत मूलक लोग रहते हैं उनके साथ भी हमें अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिए।

हमें समुद्रपार रहने वाले भारतीय लोगों के हितों की ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हम उनके अधिकारों का संरक्षण करने में असफल रहे हैं। हमें उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है।

हमारा वदेशिक कार्यालय शब्दांश अर्थों में एक परराष्ट्र कार्यालय है। वहां भारतीय 'लाबी' के अतिरिक्त सभी लाबियां अर्थात, अमरीकन लाबी अरब लाभ, रूसी लाबी हैं। वहां के सचिव है मि० आजिम हुसैन जो भावनात्मक दृष्टि से पाकिस्तान के अधिक निकट हैं। वहां पर भारतीय हितों की रक्षा करने वाले लोगों को ही रखा जाना चाहिए।

हमें अपने वैदेशिक कार्यालय में हिन्दी का अधिक प्रयोग करना चाहिऐ। बहुत से राजदूतों ने मुझे बताया है कि अंग्रेजी के प्रयोग के कारण वे अपनी गुप्त बातों को गुप्त नहीं रख सकते।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हमें भारतीय विदेशी सेवा के युवकों को अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। इस विभाग में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के एकाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए। उन लोगों को नागालैण्ड तथा काश्मीर में प्रशासनिक कार्यों पर

लगाया जाना चाहिए। अमरीका तथा रूस जैसे महत्वपूर्ण राजदूतावासों में विशिष्ठ सार्वजनिक व्यक्तियों को प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

विदेश नीति कोई दलगत प्रश्न नहीं है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इस मामले में समूचे देश को एक होना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता रहा है। मेरा सुझाव है कि सभी मामलों में सर्वसम्मति की नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि सरकार इस मामले में पहल करे और राष्ट्रीय हितों को सब से ऊपर रखे तो एक राष्ट्रीय विदेश नीति बनाई जा सकती है।।

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य अभी बोले हैं वह मुझसे सहमत होंगे कि जिस नाम का उल्लेख उन्होंने किया है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री उमानाथ : नहीं। केवल नियमों के आधार पर ही ऐसा किया जा सकता है।

सभापति महोदय : मैंने उन्हें नहीं बुलाया है।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) **:** It would have been better, had the particular name not been mentioned. Since it has now been mentioned, any wrong practice should not be established by expunging it from the record. We have been mentioning names of the officers and criticising them in the House- it is for the Minister to repudiate it. Practice of expunction in this way has not been follwed in the past and such a thing should not be done in future also.

Shri Shashibhushan Bajpai (Khargone) **:** The hon. Member should withdraw this name as it smacks of feeling of communalism.

श्री बलराज मधोक : मैं कोई गया सदस्य नहीं हूँ। मैं यह नाम लेना नहीं चाहता था परन्तु यदि मैं ऐसा न करता तो मैं अपना कर्तव्य पालन न करने का दोषी होता। मैंने राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा किया है और मंत्री महोदय को इस गलत फहमी को दूर करना चाहिये मैं यह नाम वापिस नहीं ले सकता।

श्री रा० कृ० सिंह : (फैजाबाद) : अमरीका की सीनेट और प्रतिनिधि सभा ने एक संकल्प पास किया है जिसमें वाशिंगटन में गांधी स्मारक स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है। यह संकल्प पांच वर्ष के बाद समाप्त हो गया, क्योंकि गांधी स्मारक स्थापित करने के लिये संकल्प में जितनी धनराशि की व्यवस्था की गई थी यह एकत्र न की जा सकी। इसका उल्लेख डा० प्रमोद व्यास की पुस्तक "डानिंग आन दि कैपिटल" में किया गया है। लेखक ने मुझे बताया है कि अमरीकी कांग्रेस के सदस्य श्री इमैन्युएल सैलब्ट ने, जिन्होंने मूल प्रस्ताव पेश किया था, मुझे यह आश्वासन दिया है कि यदि भारत सरकार इस परियोजना के लिये सहयोग देने को तैयार है तो वे उस संकल्प को अमरीकी कांग्रेस में फिर उठा सकते है। यदि वहाँ पर यह स्मारक स्थापित हो जाये तो इससे हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा।

महा मा गांधी को यहूदियों से सहानुभूति थी, फिर भी उनका विचार था कि यहूदियों को अरब लोगों पर थोपना गलत है। महात्मा गांधी के विचारों का आदर दिया जाना चाहिये। जानबूझ कर पश्चिम एशिया में यहूदियों का देश बनाया गया है। यह प्रदेश तीन महाद्वीपों अर्थात यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया से घिरा हुआ है। जो स्वेज पर मिलते हैं वह देश आस्ट्रेलिया, अमरीका या लैटिन अमरीका में भी बनाया जा सकता था परन्तु जान-बूझ कर ऐसा नहीं किया गया। इसराइल को अफ्रीका तथा एशिया के मध्य में इसलिये स्थापित किया गया था ताकि यह साम्राज्यवाद के मोर्चे का काम दे सके।

13 लाख अरबों को अपने देश से निकाल कर इसराइल की स्थापना की गई। जिन को अपने देश से निकाला गया वे यहुदी साम्राज्य को कैसे भूल सकते हैं ?

कुछ सदस्यों ने इसरायल का समर्थन करने की बात कही है। परन्तु उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्य, देशों ने अरब लोगों का समर्थन किया है। माननीय सदस्यों को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इसरायल का समर्थन करना हमें बहुत महंगा पड़ेगा। अरब के देशों के साथ हमारा लगभग 100 करोड़ रुपये का जो व्यापार है वह समाप्त हो जायेगा। अरब देश हमारे शत्रु हो जायेंगे और उन देशों का नेतृत्व पाकिस्तान जैसे साम्प्रदायिक देश के हाथों में चला जायेगा, जो हमारा कट्टर शत्रु है।

स्वर्गीय नेहरू की गुट–निरपेक्षता की नीति हमारे लिये हितकर सिद्ध हुई है। उस नीति के लाभ इस बात से स्पष्ट हो जाते हैं कि आज चीन के मुकाबले में रूस हमारा समर्थन करता है और पूर्वी यूरोप के देश भी चीन के विरुद्ध हमारा समर्थन करते हैं। इस नीति के कारण ही चीन आज सभी समाजवादी देशों से दूर होता जा रहा है और अधिकांश मुस्लिम और अरब देश हमारे मित्र हैं।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr Deputy Speaker *in the Chair* }

हमारा देश संसार के चार महान उदीयमान देशों अर्थात अमरीका, रूस, चीन और भारत में से एक है। नेहरू की नीतियों पर चल कर ही हम विश्व की राजनीति में महत्व-पूर्ण योगदान दे सकेंगे। हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है और हम तभी ऐसा कर सकता है जब हमारी स्वतंत्र विदेश निति हो। नये उपनिवेशवाद, जातीयता तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मुकाबला करके ही हम अपनी विदेश नीति को बल दे सकते हैं।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मागों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
15	2	श्री रामावतार शास्त्री	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों पर अत्याधिक व्यय ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
15	3	,,	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा अपर्याप्त प्रचार ।	,,
15	4	,,	वियतनाम के सम्बन्ध में भारत की विदेश नीति ।	,,
15	9	,,	गुटनिरपेक्षता का पालन न करना ।	,,
15	16	श्री बलराज मधोक	सरकार द्वारा अरब राष्ट्रों के प्रति पारस्परिक नीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रुपया ,,
15	17	,,	इसरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
15	18	,,	दक्षिण पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
15	19	,,	सरकार द्वारा पख्तूनिस्तान के प्रश्न पर अफगानिस्तान को प्रभावी समर्थन देने की आवश्यकता ।	,,
15	20	,,	नागालैंड सम्बन्धी कार्यों को गृह-कार्य मंत्रालय को सौंपने की आवश्यकता ।	,,

15	21	श्री बलराज मधोक	तिब्बत को आजाद कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपया ।
15	22	,,	सरकार द्वारा ताशकन्द घोषणा पर पाकिस्तान द्वारा अमल कराने की आवश्यकता ।	,,
15	23	,,	भारत के विदेश–स्थित दूतावासों का भारतीयकरण करने की आवश्यकता ।	,,
16	35	श्री रामावतार शास्त्री	तिब्बती शरणार्थियों को सहायता देने के नाम पर दलाई लामा को भारत में चीन विरोधी प्रचार करने की सुविधायें देना ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।
15	42	श्री ही० ना० मुकर्जी	वियतनाम में अमरीकी कार्यवाहियों की अत्यधिक और सदा बढ़ रही बर्बरता के प्रति सरकार की उदासीनता ।	100 रुपया ।
15	43	,,	अरब देशों के साम्राज्य वाद-विरोधी प्रयत्नों के साथ भारत के अटूट संबंधों का प्रभाव ।	,,
15	44	,,	अरब देशों के विरुद्ध साम्राज्यवाद-प्रेरक आक्रमण पर हुई हाल की संयुक्त-राष्ट्र बैठकें ।	,,
15•	45	,,	प्रस्तावित आणविक शस्त्रों का फैलाव रोकने संबंधी संधि के बारे में सरकार का रवैया ।	,,

15	46	,,	जर्मन प्रजातान्त्रिक गणराज्य को सम्पूर्ण राजनयिक मान्यता प्रदान करने में सरकार की निरन्तर भूल ।	,,
15	47	,,	मंगोलिया गणराज्य की राजधानी उलान-बटोर में एक परिपूर्ण दूतावास स्थापित करने में विलम्ब ।	,,
15	48	,,	विदेशों में हमारे दूतावासों पर होने वाला असमान्य रूप से भारी व्यय ।	,,
15	49	,,	चीन के साथ हमारे युद्ध से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को कम कर अन्त में सुलझाने के लिये उचित पहल करने की वांछनीयता ।	,,
15	50	,,	पाकिस्तान के साथ अधिक अच्छे संबंध स्थापित करने के मार्गोपाय ढूंढ़ने की आवश्यकता ।	,,
15	51	,,	वियतनाम में अमरीका के अकारण आक्रमण के संबंध में एक सिद्धान्तपूर्ण नीति अपनाने में असफलता ।	,,
15	52	,,	वियतनाम संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग में भारत का नेतृत्व सक्रिय बनाने में असफलता ।	,,
15	53	श्री ही० ना० मुकर्जी	उत्तर-कोरिया और कम्बोडिया के विरुद्ध बढ़ रहे अमरीकी हस्तक्षेप के भयानक परिणामों पर ध्यान देने में असफलता ।	,,
15	54	,,	दूतावासों और वैदेशिक प्रचार कार्य में सरकार की विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित भारतीयों का उपयोग न करना ।	,,

15	55	श्री ही० ना० मुकर्जी	'चीनी विस्तारवाद रोकनें' की भारत की नीति को दोहराने के भयंकर परिणाम।	100 रुपया।
15	56	,,	ब्रिटेन और अमरीका द्वारा हिन्द महासागर द्विपों पर सैनिक अड्डे बनाने के बारे में सरकार की कमजोर नीति।	,,
15	57	,,	पिल्ले समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेने में विलम्ब और विदेश सेवा को नई विचार-धारा प्रदान करने की वांछनीयता।	,,
15	58	,,	तिब्बत के प्रश्न पर सरकार के विदेश नीति के मूल सिद्धान्तों से हट जाने से खतरे।	,,
15	59	,,	हिमालय में स्थित राज्यों के साथ मित्रता के भारत के स्वभाविक रवैये को सुदृढ़ करने में असफलता।	,,
15	60	,,	अमरीकी गुप्तचर विभाग (सी० आई० ए०) की भारत में गतिविधियों पर नजर रखने और उनपर पूर्ण रोक लगाने में असफलता।	,,
15	61	,,	रीटा फेरिया और जुबिन मेहता जैसे व्यक्तियों के विदेशों में व्यवहार को रोकने में असफलता, जो भारतीय प्रतिष्ठा के बहुत ही प्रतिकूल है।	,,
15	62	श्री मी० रु० मसानी	साम्यवादी चीन की आणविक धमकी के विरुद्ध अमेरिका और रूस से गारन्टी प्राप्त करने के लिये प्रबल कदम उठाने में असफलता।	,,

15	63	,,	इसराइल और अरब देशों के बीच हुई लड़ाई में व्यक्ति-निरपेक्ष तथा निष्पक्ष रुख अपनाने और पश्चिम एशिया में उचित तथा स्थायी शांति के लिये कार्य करने में सरकार की असफलता ।	,,
15	64		भारतीय जनता के एक बड़े भाग की अविलम्ब आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनाज को जहाजों द्वारा जल्दी पहुँचाने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्वेज नहर को फिर से खोलने के लिये संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार को मनाने के लिये प्रभावी कदम उठाने में असफलता ।	,,
15	65	,,	चीन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए हमारे राजनयिकों के साथ किए गये पाशविक दुर्व्यवहार तथा बेइज्जती के व्यवहार को देखते हुये पेकिंग के साथ राजनयिक संबंधों को भंग करने में असमान फलता ।	,,
15	66	,,	चीन साम्यवादी विस्तारवाद के विरुद्ध प्रादेशिक सुरक्षा का तरीका खोज निकालने के लिये पहल करने और नेपाल, श्री लंका, बर्मा, थाइलैंड, मलयेशिया, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, दक्षिण वियत-नाम, फिलिपाइन्स, दक्षिण कोरिया, चीनी गणराज्य,	

			जापान, आस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर इसके साथ कार्य करने में असफलता ।	
15	67	श्री मीं० रू० मसानी	चीनी साम्यवादी शासन के उत्तर वियतनामी पिट्ठुओं द्वारा किये जा रहे गुरिल्ला युद्ध द्वारा आक्रमण और तोड़-फोड़ के विरुद्ध दक्षिण वियतनाम की रक्षा के मामले में उसकी सरकार तथा लोगों का समर्थन करने में असफलता ।	100 रुपया
15	68	,,	श्री दलाईलामा की तिब्बती सरकार का देश निष्कासित प्रमुख मानने में असफलता ।	,,
15	1	श्री श्रीनिवास मिश्र	सही गतिशील एवं तटस्थ विदेश नीति का अनुसरण करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
15	69	,,	विदेश स्थित मिशनों द्वारा कुशलतापूर्वक तथा शीघ्र कार्य किये जाने में असफलता ।	,,
15	70	,,	तिब्बत में किये जा रहे जाति-विनाश को रोकने के लिये ठोस उपाय करने में असफलता ।	,,

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : सभा को वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर पुनर्विचार करना चाहिये क्योंकि 33 करोड़ रुपये की धनराशि में पिछले वर्ष से लगभग 9 करोड़ रुपये की वृद्धि है। अधिकारियों के वेतन में स्वविवेक से किये जाने वाले खर्च तथा भत्तों का अनुपात बहुत अधिक है। विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में धन की कमी है। इस खर्च का स्पष्टीकरण दिया जाना जरूरी है।

सरकार ने इसराइल के आक्रमण का निरन्तर विरोध करके तथा अरब राष्ट्रों का समर्थन करके बहुत ही सम्मानजनक कार्य किया है। संसार की घटनाओं से परिचित कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि इसराइल बड़े तथा बुरे भेड़ियों के बीच एक छोटा सा निरीह मेमना है। इसके विपरीत इसराइल अरब जगत में स्थापित अमरीकी कपट का द्योतक है और अरब देशों की स्वतंत्रता के लिये सदैव खतरा है। फिलस्तीन के शरणार्थियों के साथ इसराइल जो बर्ताव कर रहा है वह निन्दनीय है। गाजा, येरूशलम तथा अन्य क्षेत्रों से जबर्दस्ती निकाली गई जनता तथा असैनिक व्यक्तियों के साथ इसराइल ने जो बर्ताव किया है वह सामान्यतया बुरा और अपमानजनक है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना काम किया है, परन्तु वहां तटस्थ राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को दो-तिहाई मत नहीं मिल सके। उसका स्पष्ट कारण यह था कि अमरीका ने, जो अपने कृपापात्रों के बचाव के लिये कटिबद्ध था, इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस तथ्य के अतिरिक्त कि यह कार्यवाही इसराइल के आक्रमण को सही बताने का दूसरा तरीका है, अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा इससे पूर्व अन्य कई अवसरों पर भी अपने रवैये से यह सिद्ध कर दिया है कि वह शीत-युद्ध के लाभ को कभी भी नहीं छोड़ सकता।

इस सम्बन्ध में भारत में भारत का रवैया मूलतः ठीक ही रहा है। यद्यपि समय-समय पर अमरीकी सहायता बन्द होने के भय के कारण वह अमरीका और ब्रिटेन की आलोचना नहीं कर सका। ऐसा प्रतीत होता है कि हम पहले दृढ़ रुख अपना लेते हैं और फिर धीरे-धीरे अपने उस रुख को नर्म करते रहते हैं। यदि हम अपने देश का प्रभावशाली चित्र कायम बनाये रखना चाहते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। हमें सिद्धान्तहीन समझौते नहीं करने चाहिये। इसरायली आक्रमण के फलस्वरूप विजित क्षेत्र को खाली कराने का प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बाकी सब प्रश्न इतने महत्वपूर्ण नहीं है और उनपर बाद में अलग से विचार किया जा सकता है।

पाकिस्तान शरारती देश है तथा हम निर्दोष हैं; यह पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध खराब होने का कारण नहीं है। कारण यह है कि अमरीका पाकिस्तान को अपने हथियार देकर भड़का रहा है जिससे कि वह भारत को गुटों से अलग रहने की नीति छोड़ने के लिये बाध्य कर सके। हम पाकिस्तान और चीन के साथ और यहां तक कि संसार के किसी भी देश के साथ हमेशा शत्रुता बनाए नहीं रख सकते। हमें पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिये पहल करनी चाहिये। काश्मीर के सम्बन्ध में हम यही कहते आये हैं कि हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारा यह रवैया कब तक बना रहेगा। शेख अब्दुल्ला को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? उन्हें तत्काल रिहा कर देना चाहिये।

तिब्बत सम्बन्धी संकल्प पर बोलते हुए श्री चागला ने सांस्कृतिक नरसंहार की बात कही थी। तिब्बत दुनियां से कोई अलग चीज नहीं है। वह भी दुनियां का एक भाग है। तिब्बत अपने विनाश के अन्तिम चरणों में से गुजर रहा था। वहां पर नृशंस अत्याचार हो रहे थे और अन्धविश्वास, भ्रष्टाचार तथा खून खराबी का बोलबाला था, जिसमें एक से अधिक साम्राज्यवादी राष्ट्र सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। आखिर वहां पर एक क्रांति आई और परिवर्तन हुए। परन्तु वैदेशिक कार्य मंत्री इन परिवर्तनों को सांस्कृतिक नरसंहार की संज्ञा देते हैं। यह दुर्भाग्य पूर्ण बात है।

हमने परमाणु शस्त्रों के फैलाव को रोकने के बारे में देश को तो क्या, इस संसद को भी विश्वास में नहीं लिया है। इस सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं, हमें कुछ पता नहीं है। हम जानते हैं कि चीन हमसे आगे बढ़ गया है और अब उसके पास उदजन बम है। आज संसार में शान्ति को खतरा बना हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम चीन के जितने भी विरुद्ध हों, हम चाहें उसकी जितनी निन्दा करें, हमें चीन की प्रगति की प्रशंसा करनी होगी। चीन में अराजकता की स्थिति होते हुए भी उन्होंने यह बड़ी भारी तकनीकी सफलता प्राप्त की है। यह ठीक है कि इस समय चीन में जो कुछ हो रहा है वह रूस के हितों के विरुद्ध है और इससे साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में बाधा पड़ रही है। अमरीका यह तो चाहता है कि अरब इसरायल को मान्यता दें परन्तु वह स्वयं चीन को मान्यता देने से इन्कार करता है।

जहां तक बम बनाने का प्रश्न है, हमारे पास न उसके लिए धन है और न ही शक्ति है। बम बनाने की होड़ में पड़ना हमारे लिये न तो व्यावहारिक है और न ही वांछनीय। हमने मास्को सन्धि पर हस्ताक्षर किये हैं। परमाणु शस्त्रों के फैलाव को रोकने वाली सन्धि पर भारत को बिना सोचे समझे हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये थे। इस मामले में हमें अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार होना चाहिये। भारत को अणु रहित क्षेत्र बनाने के लिये और अन्ततोगत्वा सभी प्रकार के निरस्त्रीकरण के लिये कार्य करना चाहिये और परमाणु बम बनाने की होड़ में नहीं पड़ना चाहिये। इस शस्त्र से सभ्यता के विनाश के सिवाय और कुछ नहीं होगा।

अब हमें चीन के साथ समझौता कर लेने का कोई तरीका निकालना चाहिये। यदि हम ऐसा न करके संरक्षण के लिये किसी और देश पर निर्भर रहते हैं जो व्यावहारिक नहीं है तो उससे विनाश हो जायेगा।

मुझे पता चला है कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष में अमरीकी लोग बड़ी संख्या में सिक्किम में जा रहे हैं। सिक्किम के अन्दर राजनीतिक उलझन है। हम अभी तक इस उलझन का समाधान नहीं कर पाये हैं। उत्तर पूर्वी सीमान्त प्रशासन, नागालैंड, मिजो तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों का मामला परस्पर जुड़ा हुआ है परन्तु हमारी सरकार इस स्थिति का सामना तदर्थ तरीके से कर रही है। सरकार ने पहले शक्ति से काम लिया और फिर समझाने बुझाने का तरीका अपनाया, परन्तु दोनों तरीके असफल रहे हैं।

तिब्बत की जनता के लिये तो हमारे विदेश मंत्री के मन में संवेदना जागृत होती है परन्तु वियतनाम में अमरीकी अत्याचारों के विरुद्ध हम कोई आवाज नहीं उठाते । उत्तर वियतनाम में द्वितीय महायुद्ध से भी अधिक बमबारी हो चुकी है। वहां पर बड़े जहरीले बम गिराये जा रहे हैं। इतना होने पर भी वियतनाम की जनता युद्ध कर रही है। सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। हमें अमरीका से कहना चाहिये कि वह उत्तर वियतनाम में स्थायी रूप से बमबारी तथा युद्ध की अन्य कार्यवाइयां बन्द कर दे। यह कार्यवाही 20 जुलाई से पहले होनी चाहिये क्योंकि उस दिन जनेवा समझौते की वर्षगांठ मनायी जायेगी।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को हम मान्यता क्यों नहीं देते ? इस देश में हम अपना वाणिज्य दूत क्यों नहीं रखते ? फिर हम मंगोलिया में अपना पूरा दूतावास क्यों नहीं स्थापित करते ? मंगोलिया हमारा मित्र राष्ट्र है। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी 1965 में वहां गई थी उन्होंने कहा था कि वहां पर एक महीने के अन्दर पूरे दूतावास की स्थापना हो जायेगी।

मैं चाहता हूं कि भारत की विदेश नीति सीधी, स्पष्ट, सुदृढ़ और सिद्धान्तों पर आधारित हो। उसमें विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में मैं सरकार के दृष्टिकोण से सहमत हूं परन्तु फिर भी मुझे सरकार की नीति में काफी कमियां महसूस होती हैं। मैंने इस सम्बन्ध में चेतावनी दी है और मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक ध्यान देगी।

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार देश की एकता और सुरक्षा की पूर्ण रूप से उपेक्षा करते हुए सरकार अपनी नीति से हटती जा रही है। सरकार ने यथार्थ स्थिति की ओर से बिल्कुल आंखें बन्द कर ली है और वह भावनाओं के परवाह में बहती चली जा रही है। सभा में भी कुछ ऐसा ही वातावरण बनता जा रहा है।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के युग में कोई भी देश अकेले नहीं रह सकता। हम जो कुछ कहते या करते हैं उसकी संसार में अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। गृह-प्रतिरक्षा तथा वैदेशिक मामलों में कुछ समन्वय होना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय इन तीनों में अभी कोई तालमेल नहीं है। इसका एक उदाहरण तिब्बत को चीन के हवाले किया जाना है जिसके फलस्वरूप एक मध्यवर्ती राज्य समाप्त हो गया। यदि उस समय हमारी विदेशी नीति प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती तो कोई ओर ही निर्णय लिया गया होता। इस समय चीन की शक्ति अधिक है और जब तक शक्ति की दृष्टि से हम चीन की बराबरी नहीं कर सकते तब तक कोई ठोस सुझाव नहीं दिये जा सकते।

{ **श्री गु० सि० ढिल्लों पीठासीन हुए** }
{ **Shri G. S. Dhillon** *in the Chair* }

असमन्वय का एक और उदाहरण संयुक्त अरब गणराज्य और इसरायल की लड़ाई के दौरान भारत द्वारा अपनाई गई नीति है । अरब राष्ट्रों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान और अब इसरायल-संयुक्त अरब गणराज्य के युद्ध से यह स्पष्ट हो गया है कि श्वेत जातियां अश्वेत जातियों की मित्र नहीं हैं। उनका हित केवल अपने व्यापार के लिये मार्ग बनाये रखने में है। वे यह चाहते हैं कि लम्बे समय के लिये शक्ति न बनी रहे जिससे अन्य देश उन पर निर्भर करते रहें ।

इसलिये मैं इस बात को उचित मानता हूं कि हमें संयुक्त अरब गणराज्य से सहानुभूति होनी चाहिये क्योंकि इसी तरीके से हम मिलकर रह सकते हैं। परन्तु इसके साथ साथ हमें इसरायल को भी आक्रामक नहीं बताना चाहिये। मेरे विचार में ऐसा करके हम अपनी सीमा से बाहर चले गये हैं। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। जिस प्रकार पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर में घुसपैठिये पहले भेजे थे, उसी प्रकार संयुक्त अरब गणराज्य ने खाड़ी पहले बन्द की थी और इसरायल की सीमा पर अपनी सेना उतारी थी। जम्मू की सामरिक रेखा को बचाने के लिये हमने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पहले पार की थी और इसी प्रकार इसरायल ने खाड़ी को खुलवाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार की थी। इसरायल ने अपने बचाव के लिये अन्तराष्ट्रीय सीमा पार की थी। इसलिये ऐसा करने के लिये हमें इसरायल की निन्दा क्यों करनी चाहिये ? यदि अपनी सुरक्षा के लिये संयुक्त अरब गणराज्य भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करता है तो हमें उसे आक्रामक नहीं कहना चाहिये।

हमें पाकिस्तान से यह बात तो सीखनी चाहिये कि जबकि हम तो अमरीका रूस और तथा संयुक्त अरब गणराज्य और इसरायल के साथ एक-साथ मित्रता स्थापित नहीं कर सके परन्तु वह अमरीका रूस और चीन के साथ भी मित्रता रखने में सफल हो गया है।

एशिया में हाल ही घटनाओं से उत्पन्न स्थिति में हमें अपने अकेलेपन की सीमा तोड़ देनी चाहिये। हमें चीन जैसे देश के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है जिसके लिये मानव अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। हाल ही में पेकिंग में हमारे दूतावास के साथ हुए व्यवहार से, बर्मा, हांगकांग में ग्रेट ब्रिटेन, इन्डोनेशिया, नेपाल आदि में चीनियों के व्यवहार से और परमाणु बम के विस्फोट से हमें पता चलता है कि एशिया, दूर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया को चीन से कितना बड़ा खतरा है। इन परिस्थितियों में हमें अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लेना चाहिये। हमें चीन के विरुद्ध दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में प्रादेशिक प्रतिरक्षा व्यवस्था बनाने में कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिये। हमें आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेंड और जापान के सक्रिय समर्थन से भारत, नेपाल, बर्मा, थाइलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इन्डोनेशिया और फिलिपाइन्स को मिलकर एक सन्धि करनी चाहिये। यह वैदेशिक कार्य मंत्रालय की परीक्षा है। वास्तव में यहां यथार्थ स्थिति की अवहेलना करके नारों पर ज़ोर दिया जा रहा है। इस मेरे सुझाव से गुट-निर्पेक्षता की नीति का अतिक्रमण नहीं होगा। मैं न तो अमरीका के साथ और न रूस के साथ गुट बनाने के पक्ष में हूँ बल्कि मैं गैर और गर रूसी अमरीकी गुट बनाने के पक्ष में हूँ।

जहां तक 1954 के चीन के साथ समझौते का सम्बन्ध है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि चीन ने इस समझौते को अपनी तरफ से रद्द कर दिया है। किन्तु हम फिर

भी उसी पर चिपके हुए हैं। इसलिये ऐसी स्थिति में यदि सिक्कम और भूटान समझौतों को नये सिरे से मूल्यांकन करना चाहते हों, तो यह स्वाभाविक ही है। इसलिये विदेशों के साथ सम्बन्धों और हमारी प्रतिरक्षा के खतरे का परस्पर समन्वय होना ही चाहिये।

काबुल, तिब्बत, और बर्मा और श्रीलंका से लौट कर भारत में आने वाले शरणार्थियों का मामला दूरदृष्टिता के अभाव का ही एक और उदाहरण है। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह भारत में शरणार्थियों को स्वीकार करने के स्थान पर इस बात को सुनिश्चित करता कि विदेशों में रहने वाले शरणार्थी बनते ही नहीं, नहीं तो निकट भविष्य में इन पर खर्च अत्यधिक बढ़ जायेगा। हमें अफ्रीकी राज्यों के साथ मित्रता बनाये रखनी चाहिए परन्तु जिस ढंग से हम विदेशों में भारतीय लोगों के मामले के साथ निपट रहे हैं तो मेरे विचार में अफ्रीका से भी भारतीय लोग आने लगेंगे। इसलिये हमें राजनयिक दृष्टि से इस मामले पर विचार करना चाहिये।

Shri Abdul Ghnai Dar (Gurgaon) : Our country has always been helping African countries in their freedom struggle. But it is not understood why have we been failed to follow that policy in the case of Tibet and why have we allowed China to grasp Tibet. If we had to adopt this policy, we should have not granted asylum to Dalai Lama. These two policies are self-contradictory.

I agree that India has raised its voice against the American atrocities in North Viet Nam but why India kept silent when Russia committed some thing in Hungary ? I cannot follow this.

I agree that we should not object to the existence of Israel. But may I know the reason why have the Arabs been displaced forcibly from the place where Israel is existing? America has been trying to establish bases everywhere. Americans are now committing atrocities. It will, therefore, be folly to endorse their policy. All the military equipment, with which Israel fought, was supplied by western countries. I agree that India should have not branded Israel as aggressor because President Nasser had not branded China and Pakistan as aggressors when they attacked on us. But if India is to call a spade a spade, There is no harm if India has branded Israel as aggressor.

So far the question of Kashmir is concerned, it is unfortunate that Pakistan has occupied a greater part of that State but we have been failed to convince the world about this fact. Kashmir is integral part of India but the present situation has been created only because of weak policy followed by our Government.

We should try to establish better relations with Pakistan because if we achieve success in this matter, it will go against the interests of China. We should not, therefore, be provoked by the actions of Pakistan. If Pakistan commits any folly, we should not fall in line with her. We should pursue a policy which is proper and justified in our own view. We should continue to establish good neighbourly relations with Pakistan and China.

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : यदि तिब्बत के सम्बन्ध में जनता की राय ली जाये तो पता चलेगा कि आम जनता की यही राय है कि तिब्बत में दलाई लामा को अपनी पुरानी स्थिति प्राप्त हो जाये। इसका कारण यह है कि हमारे देश की जनता यह महसूस करती है कि हमारी सरकार ने तिब्बत के सम्बन्ध में सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया।

तिब्बत के मामले जिस आधार पर चीन के साथ समझौता हुआ था उसका नाम पंचशील है। यह एक बहुत ही पवित्र नाम है जिसके साथ संसार का अध्यात्मक और सांस्कृतिक इतिहास सम्बद्ध है। इस पंचशील का सबसे पहला सिद्धान्त यह है कि 'जो मुझे नहीं दिया गया, मैं उसे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करूंगा'। मेरे विचार में चीन द्वारा इस सिद्धांत का उल्लंघन किये जाने के कारण ही पं० जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु हुई।

वैदेशिक-कार्य मंत्री ने कहा है कि तिब्बत के बारे में हम मनमाना इतिहास नहीं बना सकते। परन्तु हम चीन द्वारा बताये गये इतिहास को ही क्यों स्वीकार करें? हमें अपने इतिहास के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये। हमारे इतिहास के अनुसार तिब्बत चीन की अपेक्षा भारत का अधिक मित्र रहा है। प्राचीनतम इतिहास से यह पता चलता है कि अध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से तिब्बत भारत का मित्र रहा है। भारतीय साहित्य से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। तिब्बत का प्राचीन नाम कुरुवर्षा और उत्तरकुरू बताया जाता है। अब भी भारतीय ढंग से वहां पूजा आदि की जाती है।

एक बार जब श्री अरविन्द घोष तिब्बत की सीमा तक गये थे तो उन्होंने वे समाचार पत्रों को एक वक्तत्व दिया था कि चीन वहां से भारत पर आक्रमण करेगा। यह वक्तव्य 1950 में दिया गया था। इसके अतिरिक्त 1954 में नेहरू-चाऊ-एन-लाई करार के पश्चात् मैं जब भारत तथा पाकिस्तान सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष से मिला था तो उन्होंने कहा था कि इस करार के बहुत विनाशकारी परिणाम होंगे।

लोकमान्य तिलक का जीवन दर्शन गीता पर आधारित था। उनका कहना था कि "दूसरों के साथ मेरा सम्बन्ध वही है जो उनका मेरे साथ है"। मंत्री महोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि तिलक ने जो नीति अपने लिये बनाई थी, क्या हम उसे वर्तमान स्थिति में अपने ऊपर लागू कर सकते हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाकार) : अध्यक्ष महोदय, जब हमारे देश ने 1947 में गुट सरपेक्षण की नीति अपनाई थी, तो उस समय उसका अनुसरण करने वाले बहुत कम देश थे, परन्तु आज अनेक देशों में उसका अनुसरण हो रहा है। अफ्रीकी एशियाई देशों में से अधिकांश ने इस विचारधारा से स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त सह-अस्तित्व का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन भारत ने किया है, अब एक वास्तविकता बन गया है और विश्व के महान राष्ट्र रूस तथा अमरीका एक दूसरे के निकट आ रहे हैं।

अरब राष्ट्रवादियों से हमारे निकटतम सम्बन्धों के कारण पश्चिमी साम्राज्य एशिया में बढ़ने नही पाया है। मालूम नहीं, चीन किस प्रकार के समाजवाद को समझता है परन्तु उसने अपने परम्परागत विस्तारवाद को बहुत पाशविक तरीके से आगे बढ़ाया हो। चीनी सरकार ने एशिया के साथ शीतयुद्ध छेड़ रखा है और अमरीका और दूसरे पश्चिमी देशों की यह आकांक्षा पूरी कर रहा है कि एशिया के देश आपस में लड़ते रहे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और भारतीय राजनीतिकों को कोई ऐसा उचित तरीका निकालना चाहिये जिससे पश्चिमी एशिया या किसी अन्य स्थान में बड़े राष्ट्र हस्तक्षेप न कर सकें। हम नहीं चाहते

कि अमरीका की वियतनाम तथा इसराइल के समर्थन में आक्रामक नीति को उस उपमहाद्वीप में निर्बाध रूप से चलने की अनुमति दी जाये। जैसा कि प्रोफेसर टायनबी ने कहा है कि पश्चिमी साम्राज्यवाद की सबसे बुरी आक्रामक प्रवृत्ति से यहूदियों का मामला और उलझ जायेगा। पश्चिमी देशों ने यहूदियों की समस्या का यह हल सोचा है कि यूरोप से यहूदी लोगों को लाकर उस स्थान पर बिठा दिया जाये जो अरब देशों का अंग है।

हमने सदा अरब देशों का समर्थन किया है क्योंकि वे प्रसारवाद के विरुद्ध अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसराइल द्वारा अरब देशों के क्षेत्र पर कब्जा किये जाने के बाद उसने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसका उत्तर क्या है ? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये यह सम्भव है कि वह इसराइल द्वारा कब्जा किये जाने वाले क्षेत्र उसके कब्जे में रहने दे ? यह सम्भव है कि इसराइल को मान्यता दी जाये परन्तु इसके प्रसारवाद को रोकना आवश्यक है। यदि पश्चिमी देश इसकी गारंटी देने में असमर्थ हैं तो क्या एशियाई देश अपने ऊपर इस बात की जिम्मेवारी नहीं ले सकते कि इसराइल के विस्तारवाद को रोका जाये।

हमें चीन के साथ परमाणु शस्त्रों की होड़ में नहीं पड़ना चाहिये, प्रतिरक्षा के मामले में यह बात सिद्ध हो गई है कि इस सम्बन्ध में किसी भी देश के लिये आज के विश्व में आत्म-निर्भर होना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि कोई भी देश सम्भवतः किसी भी तरह के आक्रमण के विरुद्ध आणविक सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि उनके अपने निजी दृष्टिकोण हैं। इन्डोनेशिया, बर्मा तथा नेपाल में जो कुछ हुआ है उसके बाद हम चीन के बारे में यह समझने का अधिकार रखते हैं कि चीन के आक्रमण का सामना सैनिक शस्त्रों की बजाये अन्य शस्त्रों से भी किया जा सकता है।

हमारे लिये अपने सभी पड़ोसियों से सम्पर्क बनाये रखना तथा राजनयिक और वाणिज्यिक स्तर पर एक दूसरे के निकट आने के प्रयत्न करना आवश्यक है, क्योंकि वाणिज्यिक स्तर पर ही हमें अपने सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ बनाने हैं।

रूस पाकिस्तान तथा काश्मीर के मामले में अपनी नीति बदलने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिये यह अनिवार्य है कि हमारी कूटनीति और अधिक गतिशील तथा प्रभावी हो। हमारे राजनयिकों को पश्चिम के समर्थन का रवैया त्याग देना चाहिये। यदि हमें विश्व में कोई महत्वपूर्ण योगदान करना है तो अफ्रीका तथा एशिया के सभी देशों को साथ लेकर चलना चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Strengthening of defence arrangements, improving trade and economic relation with foreign countries and protection to the people of Indian origin in other countries are three test of success of foreign policy, but miserably failed in all those spheres.

China is not having good relations with Indonesia, Burma and Combodia. We should take advantage of this situation in those countries and strengthen our interests. It is disappointing that China division of the Ministry of External Affairs has not been able to formulate any clear policy which is to be adopted with regard to our relations with China.

I would not emphasise the fact that the policy of non-allignment is not being applied in the matter of establishing diplomatic relations with Taiwan or Formusa, but I would put emphasis on the question of using her as a window on China. It will, therefore, be in our interest to establish certain relations with country. Apart from that Chiany-Kai-Sheik has full sympathy with our country It is unwise to have no relations with her at all.

Our West Asia policy in the time of Shri Jawar Lal Nehru was based on the personal friendship of Shri Nehru and President Nassar. We should not continue to adopt the same policy and we should revise this policy keeping in view the changed circumstances. Our foreign policy is based on the principle of co-existence. The Arab countries are opposing the concept of co-existence. Therefore our foreign policy cannot be the same as that of Arab countries.

The Government should learn a lesson from the fate of our resolution in U. N. We should favour the internationalisation of the Suez Canal.

Pillai Committee made a number of recommendations with regard to our foreign services. I would like to know the improvements made in view of those recommendations.

Our neighbouring countries like Burma, Thailand, Cambodia, Japan, Bhutan, Jawa, Sumatra, Ceylon and Nepal are very keen to strengthen cultural relations with India. The Ministry of External Affairs has taken no steps to improve cultural relations with the neighbouring countries. Cultural ties with those countries can prove more useful than political relations.

The Ministry should safeguard the interests of Indians in other countries. The Government should provide necessary facilities for bringing the property of those Indians who are being compelled to leave the countries in which they had been staying for years.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नागा विद्रोहियों द्वारा पुलिस कर्मचारियों की हत्या

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter Urgent Public Importance and request that he may make a statement in regard thereto :–

"reported killing of 23 policemen of the Central Reserve Police in an ambush and looting of arms and ammunition by Naga hostiles in Manipur."

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 12 जुलाई को केन्द्रीय रक्षित दल की एक टुकड़ी मनिपुर के तामेन्गलांग सबडिवीजन में इम्फाल-तामेन्गलांग सड़क पर 44वें मील सें 62 वें मील तक दो गाड़ियों में एक टेलीफोन लाइन मरम्मत करने वाले दल का संरक्षण करने के लिये जा रही थी, विद्रोहियों ने 52 वें मील के निकट सड़क रोक रखी थी और

उन्होंने घात लगाकर हमारे सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला कर दिया। सड़क की दोनों ओर से उन्होंने छोटे शस्त्रों तथा स्वचालित हथियारों से गोली चलाई। दल के 23 सदस्य वहीं मारे गये और केन्द्रीय रक्षित दल का केवल एक सिपाही जो बच गया, वह 44 वें मील पर वापिस आ गया। वह भी बुरी तरह घायल हो गया था। एक गाड़ी पूरी तरह जल गई तथा विद्रोहियों ने शस्त्र तथा गोलाबारूद लूट लिया। सिविल अधिकारियों की सहायता के लिये सैनिक दस्ते बुलाए गए हैं और वे अपराधियों की खोज कर रहे हैं।

उसी दिन शाम को उसी सड़क पर 32 वें मील पर विद्रोहियों ने एक और दल पर गोली चलाई। टेलीफोन लाइन दल का एक सदस्य मारा गया और पांच घायल हो गये। तामेंगलांग सब-डिवीजन, जहां यह घटनायें हुई है, उस क्षेत्र में स्थिति है जिसे कार्यवाही निलम्बन समझौते में शामिल किया गया है। इसलिये सरकार को इन घटनाओं से बहुत ही चिन्ता हुई है। प्रधान मंत्री दुखी परिवारों की तुरन्त सहायता के लिये 24,000 रुपये भेज रही है।

Shri Sidheshwar Prasad : This House has repeatedly expressed grave concern over increase in the area of operation of the hostile Nagas. They are now operating in Manipur. I would like to know the reasons why the Government has not been able to prevent such incidents.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें इस मामले की बहुत चिन्ता है कि यह कार्यवाही निलम्बन सम्बन्धी करार घोर उल्लंघन है।

श्री हेम बरुआ : युद्ध-विराम समझौते को मणिपुर क्षेत्र में भी लागू करने की अनुमति क्यों दी गई।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम इस बात को ध्यान में रखेंगे।

श्री स० कुण्डू (बालासौर)**:** मैं जानना चाहता हूं कि क्या विद्रोहियों के साथ युद्ध विराम समझौता पूर्णतया समाप्त कर दिया जायेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इन सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj)**:** I would like to know whether the Government will reconsider the policy in this regard.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सरकार इन मामलों को बहुत गम्भीर समझती है और हम इन पर पुनर्विचार करेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 17 जुलाई, 1967/2 अषाढ़, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 17th July, 1967/Asadha 2, 1889 (Saka).

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

चतुर्थ माला

Fourth Series

खंड 6, 1967 / 1889 (शक)

Volume (V), 1967/1889 (Saka)

[4 जुलाई, से 15 जूलाई 1967/13 से 24 आषाढ़ 1889 (शक)]

[July 4 to 15, 1967/Asadha 13 to 15, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 6 में अंक 31 से 40 तक हैं)

(Volume (V) contains Nos. 31 to 40)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

5558

P.L.S. 48. VI. IV. 67 (N)
600

© 1967 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–३ द्वारा मुद्रित ।

© 1967 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, DIAMOND PRINTING PRESS, JAIPUR-3